भारतीय वैश्विक
परिषद

SPARU HOUSE PAPER

छोटे खाड़ी देशों की बदलती विदेश नीति

ओमान की केस स्टडी

डॉ. लक्ष्मी प्रिया

भारतीय वैश्विक
परिषद

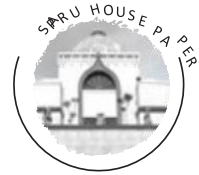

छोटे खाड़ी देशों की बदलती विदेश नीति

ओमान की केस स्टडी

डॉ. लक्ष्मी प्रिया

भारतीय वैश्विक
परिषद

भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच. एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रख्यात बुद्धिजीवियों के समूह द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान एवं विचार भंडार के रूप में काम करना था। परिषद आज आंतरिक संकाय के साथ- साथ अतिथि विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान के कार्य करती है। यह नियमित रूप से बौद्धिक गतिविधियों का आयोजन करता है जिसमें सम्मेलन, सेमिनार, गोलमेज सम्मेलन, व्याख्यान भी शामिल होते हैं। परिषद प्रकाशन कार्य भी करता है। इसके पास समृद्ध पुस्तकालय है, इसकी वेबसाइट सक्रिए रूप से काम करती है और यह ***इंडिया*** नाम की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों में विकास करने हेतु आईसीडब्ल्यूए ने अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ- समूहों और शोध संस्थानों के साथ 50 से अधिक अनुबंध किए हैं।

परिषद की साझेदारी भारत के अग्रणी शोध संस्थानों, विशेषज्ञ समूहों और विश्वविद्यालयों के साथ भी है।

छोटे खाड़ी देशों की बदलती विदेश नीति
ओमान की केस स्टडी

प्रथम प्रकाशन, जून 2024

© भारतीय वैश्विक परिषद आईएसबीएन: 978-93-83445-

85-1

सर्वाधिकार सुरक्षित। कॉपीराइट स्वामी की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना इस प्रकाशन के किसी भी अंश को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम- इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा, पुनरुत्पादित, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में तथ्यों और रायों की जिम्मेदारी पूरी तरह से लेखकों की है और उनकी व्याख्या आवश्यक रूप से भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली के विचारों या नीति को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

भारतीय वैश्विक परिषद, सप्रू हाउस,

बाराखंबा रोड, नई दिल्ली 110001, भारत

दूरभाष: +91-11-2331 7246 | फैक्स: +91-11-2332 0638

www.icwa.in

विषयवस्तु

सार 5

परिचय 7

खंड I :

ओमान की विदेश नीति के निर्धारक 15

खंड II :

ओमान की विदेश नीति का विकास 43

खंड III :

ओमान की विदेश नीति की बदलती स्थिति 51

निष्कर्ष:

भारत के लिए नीतिगत अनुशंसाएं 73

लेखक के बारे में 95

सार

खाड़ी क्षेत्र तेज़ी से बदल रहा है और छोटे जीसीसी देश दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को बदलती परिस्थिति के अनुसार रूप दे रहे हैं। यह शोधपत्र खाड़ी देशों की बदलती विदेश नीति का विश्लेषण करने वाले एवं ओमान पर ध्यान केंद्रित कर लिखे गए शोधपत्रों की श्रृंखला में तीसरा शोधपत्र है। शोधपत्र तीन खंडों में विभाजित है। पहले खंड में भूगोल, जनसांख्यिकी, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सहायता, क्षेत्रीय माहौल एवं अंतरराष्ट्रीय माहौल समेत ओमान की विदेश नीति के निर्धारकों पर चर्चा की गई है। दूसरे खंड में ओमान की विदेश नीति के विकास का वर्णन किया गया है। तीसरे खंड में ओमान की विदेश नीति की बदलती स्थिति पर चर्चा की गई है। आखिर में, शोधपत्र निष्कर्ष खंड में भारत- ओमान संबंधों पर नीतिगत अनुशंसाएं प्रदान करता है।

मुख्य शब्द: विदेश नीति, छोटे देश, ओमान, भारत

परिचय

छोटे देश अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक व्यवस्था का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र के आधे से अधिक सदस्य देश ऐसे ही छोटे देश हैं। विश्व बैंक ने पचास देशों को छोटे देशों के रूप में सूचीबद्ध किया है।[1] छोटे देशों को मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही तरह से परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रमंडल छोटे देशों की सूची में शामिल किए जाने के लिए जनसांख्यिकी (1.5 मिलियन/15 लाख या उससे कम) को एक मानदंड मानता है और इसमें 33 छोटे देश शामिल हैं।[2] संयुक्त राष्ट्र में स्वैच्छिक एवं अनौपचारिक समूह द फोरम ऑफ स्मॉल स्टेट्स (एफओएसएस/FOSS) ऐसे देशों को छोटे देश बताता है जिनकी आबादी 1 करोड़ (10 मिलियन) से कम हो इस समूह की सूची में 108 देश शामिल हैं।[3] सीमित क्षेत्र और संसाधनों के कारण छोटे देशों को अलग- अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अक्सर वे विशेष कारणों से समूह बनाते हैं। उदाहरण के लिए, 1990 के दशक में छोटे द्वीप देशों का गठबंधन बनाया गया था। यह छोटे द्वीपीय देशों पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन के हानिकारक सामाजिक- आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण नीतियों को प्रभावित करने पर ध्यान देता है। साल 2009 में, सिंगापुर ने संयुक्त राष्ट्र के 30 छोटे और मध्यम आकार वाले सदस्य देशों का एक अनौपचारिक समूह बनाया था जिसे ग्लोबल गवर्नेंस ग्रुप (3जी/3G) कहा गया।[4] इसी प्रकार, छोटे द्वीपीय विकासशील देश (एसआईडीएस/SIDS) 39 देशों और 18 सहयोगी सदस्यों का एक विशेष समूह है, जो विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कमियों का

छोटे देश अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक व्यवस्था का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग हैं।
संयुक्त राष्ट्र के आधे से अधिक सदस्य देश ऐसे ही छोटे देश हैं।

सामना कर रहे हैं और कैरीबियाई, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर एवं दक्षिण चीन सागर (एआईएस) में स्थित हैं।[5]

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, छोटे देशों के अध्ययन को तीन चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है:1959-1979, 1979-1992 और 1992- अ ब तक। पहले चरण में, अध्येताओं ने शास्त्रीय यथार्थवाद के सैद्धांतिक प्रतिमान के माध्यम से छोटे राज्यों का अध्ययन किया, छोटे देशों को उनकी सैन्य और आर्थिक कमियों के आधार पर परिभाषित किया और तर्क दिया कि छोटे देशों की नीतियों को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में बड़े देशों के व्यवहार के कार्य के रूप में समझा जा सकता है। इस दौरान, छोटे देशों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सीमांत अभिनेताओं के रूप में देखा गया। दूसरे चरण के दौरान, अध्येताओं ने छोटे देशों के मुद्दों की व्यापक रूप से नव-यथार्थवादी दृष्टिकोण से पड़ताल की, जबकि तर्क दिया कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की संरचना को विश्लेषणात्मक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तीसरे चालू चरण में छोटे देशों के अध्ययन को फिर से जीवंत किया जा रहा है, जो रचनात्मकता के एक नए सैद्धांतिक प्रतिमान के उद्भव से प्रेरित है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि छोटे देशों में व्यावहारिक राजनीतिक विकास उन्हें समझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत की क्षमता से आगे निकल रहे हैं।[6]

छोटे देशों पर कई अध्ययन किए गए हैं और हे की किताब पैराग्वे, कैरीबियन, पनामा, लक्ज़मबर्ग, ऑस्ट्रिया, गाम्बिया, जॉर्डन और लाओस जैसे देशों की विदेश नीति व्यवहार पर चर्चा करती है।[7] टॉम लैंग के अनुसार, छोटे देशों को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः व्युत्पन्न देश जो किसी महाशक्ति के साथ संबंधों पर निर्भर रहकते हैं, सामूहिक देश जो कभी- कभी संस्थाओं के माध्यम से सहायक देशों के गठबंधन बनाते हैं और आंतरिक देश जो निर्णय को प्रभावित करने के

छोटे देश घनिष्ठता बनाए रखने में सक्षम होते हैं और शत्रुता को दबाने, अपने विचारों को स्थगित रखने, असहसमति को नियंत्रित करने एवं स्थिरता और समझौते के हित में विवाद से बचने में विशेषज्ञ बन जाते हैं।

लिए परिसंपत्तियों पर निर्भर रहते हैं।[8] छोटे देश घनिष्ठता बनाए रखने में सक्षम होते हैं और शत्रुता को दबाने, अपने विचारों को अलग रखने, असहमति को नियंत्रित करने एवं स्थिरता और समझौते के हित में विवाद से बचने में विशेषज्ञ बन जाते हैं।[9] केसिया एफ्रेमोवा का तर्क है कि एक "बफर सिस्टम" के अंतर्गत, छोटे देश महाशक्तियों के व्यवहार को इस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं जिससे महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता कम हो जाए।[10]

छोटे देशों (कोसोवो) की विदेश नीति पर अल्फ्रेड मार्लेकु का काम बहुराष्ट्रीय समझौतों को सुरक्षित करने और बहुराष्ट्रीय संस्थाओं में शामिल होने की उनकी प्रवृत्ति पर केंद्रित है, साथ ही सुरक्षा, साझेदारी और संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिए बड़े देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका पर विश्वास करने की प्रवृत्ति पर भी ध्यान देता है।[11] छोटे देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा पर इदरीस डेमिर के अध्ययन के अनुसार, बाल्टिक देशों की सुरक्षा धारणाएं छोटे देशों की सुरक्षा गणनाओं के लिए एक तार्किक आधार प्रदान करती हैं।[12] इस तथ्य को ध्यान में रखना दिलचस्प है कि थोरहॉल्सन और विवेल का मानना है कि एक छोटा देश होना "एक विशिष्ट समय-स्थान दोनों में मौजूद संदर्भ" से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे छोटे देशों को कठोर परिभाषाओं से मुक्त देखते हैं।[13] मिरियम फैंडियस एल्मन ने संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रमुख शक्ति की नज़र से पूर्वी यूरोप के छोटे राज्यों की विदेश नीति को देखने की कोशिश की है।[14] इसी प्रकार, सुसी डेनिसन ने छोटे राज्यों के प्रति यूरोपीय संघ की विदेश नीति पर काम किया है।[15] इसके अलावा, लायी युन यी ने संरचनात्मक यथार्थवादी दृष्टिकोण से कंबोडिया, सिंगापुर और वियतनाम जैसे छोटे देशों की विदेश नीति आचरण की पड़ताल की है और

दक्षिण चीन सागर विवाद को केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल किया है।[16] बेक फॉक्स (1959) का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इस बात पर गौर किया गया है कि अपेक्षाकृत छोटे और सैन्य रूप से कमज़ोर देशों की सरकारें संकट के समय में भी महाशक्तियों के मजबूत दबाव का विरोध कैसे कर सकती हैं। यह पड़ताल द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की, फ़िनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और स्पेन के अनुभवों पर आधारित है।[17] यूरोप के छोटे देशों पर कई अध्ययन किए गए हैं; उदाहरण के लिए, गेज़िम विलासी ने यूरोपीय संघ और उससे बाहर के छोटे देशों पर काम किया है।[18]

जहाँ तक छोटे देशों के व्यवहार की विशेषताओं का प्रश्न है, थोरहॉल्सन और स्टीन्सन के अनुसार, छोटे देश बहुपक्षीय संगठनों के प्रति प्राथमिकता दिखाते हैं क्योंकि बड़े देशों की तुलना में उनके लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त करना कठिन होता है।[19] अप्रैल 2022 में "छोटे देश, बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून" पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अनौपचारिक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करते हुए मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री श्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा था कि छोटे देश अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रधानता के माध्यम से बहुपक्षवाद को मजबूत करते हैं।[20] जियोर्जी ग्वालिया, डेविड सिरोकी, बिदज़िना लेबनिडेज़ और ज़ुराब इआश्विली के अनुसार, देश और व्यक्तिगत स्तर के चर छोटे देशों के विदेश नीति व्यवहार को समझाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और जॉर्जिया जैसे छोटे देश कभी- कभी बैंडवैगन के बजाय संतुलन बनाना चुनते हैं, खासकर जब अभिजात वर्ग की विचारधारा विदेश नीति के निर्माण में गहराई से अंतर्निहित होती है।[21] इसी प्रकार,

आर्ची डब्ल्यू. सिंपसन ने कहा कि तटस्थता या गैर- पक्षपात का उपयोग आमतौर पर छोटे देशों द्वारा

> छोटे देश बहुपक्षीय संगठनों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि बड़े देशों की तुलना में उनके लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त करना कठिन होता है।

अन्य देशों की सत्ता की राजनीति से बाहर निकलने के साधन के रूप में किया जाता है, जबकि वे तदर्थ, विधिक और वास्तविक तटस्थता की व्याख्या करते हैं।[22]

हालाँकि, सभी छोटे देश एक ही जैसा व्यवहार नहीं करते हैं; हौगेविक, कुसिक, रायक और शिया ने एस्टोनिया और नॉर्वे के यूएनएससी के विभिन्न दृष्टिकोणों पर काम किया है।[23] जेसी और ड्रेयर ने 20वीं सदी में दुनिया भर से सात केंद्रित केस स्टडीज़ पर काम किया है। स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, फ़िनलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्ज़ियम, इथियोपिया, सोमालिया, वियतनाम, बोलीविया और पैराग्वे की विदेश नीति विकल्पों की पड़ताल के माध्यम से, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि महान शक्ति राजनीति पर आधारित यथार्थवादी सिद्धांत अधिकांश मामलों में छोटे देशों के व्यवहार को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। जब छोटे देशों को बड़े देशों, युद्धरत देशों से खतरा होता है तो छोटा देश सामाजिक रचनावादी सिद्धांत की भविष्यवाणियों के अनुसार व्यवहार करता है; जब छोटे देश एक- दूसरे को धमकाते हैं, तो वे यथार्थवादी भविष्यवाणियों के अनुसार व्यवहार करते हैं।[24]

विदेश नीति निर्धारक
भूगोल
समाज और जनसांख्यिकी
राजनीति
अर्थव्यवस्था
सुरक्षा और सहायता
क्षेत्रीय माहौल
अंतरराष्ट्रीय माहौल

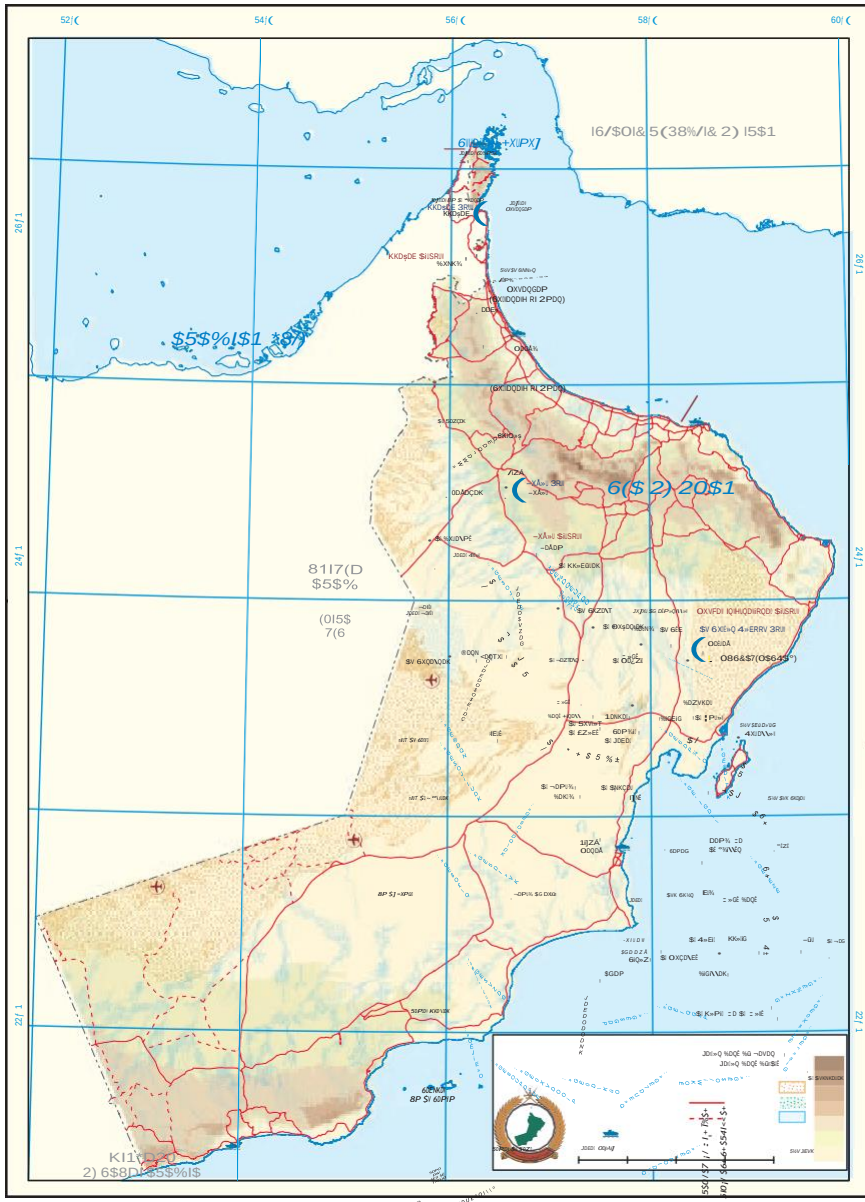
52/(
54/(
56/(
58/(
60/(
26/1
24/1
22/1
20/1
I6/$OI& 5(38%/I& 2) I5$1
6($ 2) 20$1
5%I$1 8%
81I7(D
5%
(0I5$
7(6
KI1(D2)
2) 6$8DI$5$%I$
8P SI 6P1P
6$ DXTP 3RII

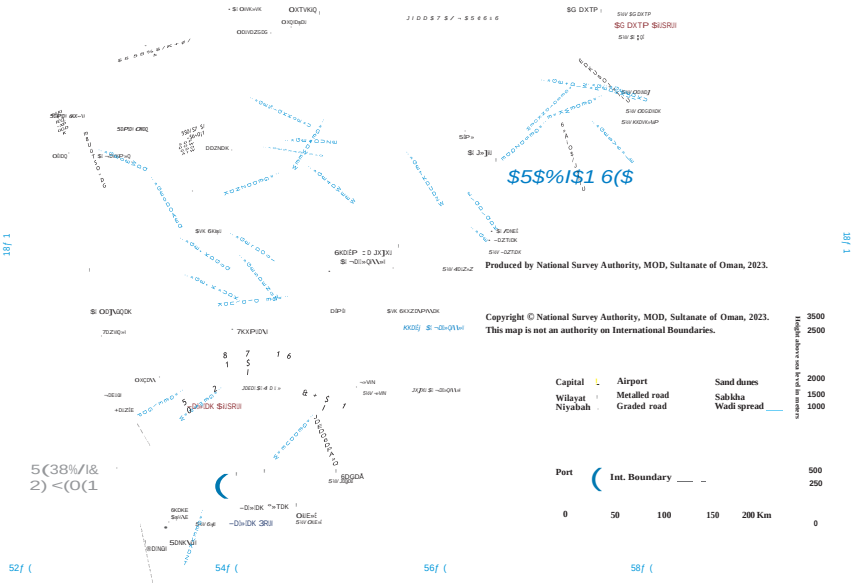

चित्र 1: ओमान सलतन का मानचित्र, 2023

स्रोत: ओमान मंत्रालय, 2023, https://fm.gov.om/about-oman/state/map-of-oman/ पर उपलब्ध

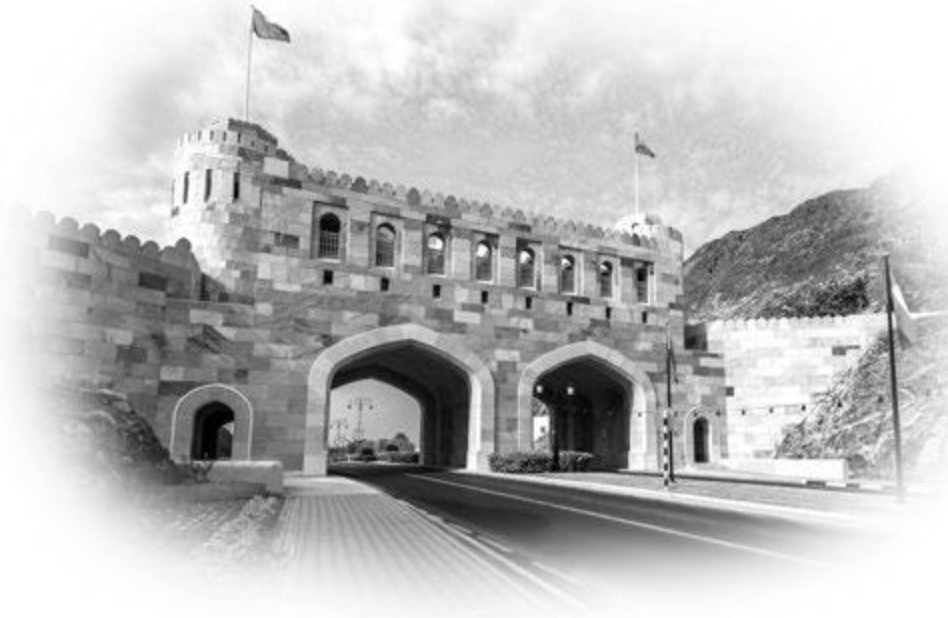

खंड I

ओमान की विदेश नीति के निर्धारक

भूगोल

भूगोल किसी भी देश की विदेश नीति के व्यवहार को परिभाषित करता है और पश्चिम एशिया के अस्थिर क्षेत्र में विदेश नीति निर्माण में इसका बहुत महत्व है। यह न केवल अंतर- क्षेत्रीय और अंतर- क्षेत्रीय भू- राजनीतिक कुशलता तय करता है बल्कि भू- आर्थिक रणनीतियों को आकार देने में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। निकोलस जे स्पाइकमैन के अनुसार, किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों में क्षेत्रीय स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका कहना है कि मंचूरिया की विदेश नीति तैयार करने वाले व्यक्ति ने जापान और रूस पर नज़र रखते हुए ऐसा किया था और बेल्ज़ियम का हर अंतरराष्ट्रीय संकेत इस तथ्य से निर्धारित होता है कि वह फ्रांस और जर्मनी एवं ग्रेट ब्रिटेन के चैनल के बीच बसा है। मध्य अमेरिका के देश एक पल के लिए भी यह नहीं भूल सकते कि उनके उत्तरी क्षेत्र पर एक महाशक्ति का कब्ज़ा है, न कि कई शक्तियों का, जिन्हें वे एक- दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर सकते हैं, जैसा कि उनके यूरोपीय समकक्ष बाल्कन देश समय- समय पर अपने उत्तरी पड़ोसियों के साथ करते रहे हैं।[25]

इसी तरह, पश्चिम एशियाई क्षेत्र के देशों और छोटे देशों की विदेश नीति निर्माण में भूगोल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र में कई क्षेत्रीय विवाद चल रहे हैं। इज़रायल और फिलिस्तीन के लिए, भूमि सीमा और क्षेत्रीय अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है और 1948, 1956, 1967 और 1973 में हुए युद्धों के कारण रही है। जीसीसी के छोटे देश

भूगोल किसी भी देश की विदेश नीति के व्यवहार को परिभाषित करता है और पश्चिम एशिया के अस्थिर क्षेत्र में विदेश नीति निर्माण में इसका बहुत महत्व है।

यह बहुत सहजता के साथ कहा जा सकता है कि ईरान और जीसीसी देशों की विदेश नीति फारस की खाड़ी की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखे बिना तय नहीं की जा सकती। इसी प्रकार, छोटे जीसीसी देशों की विदेश नीति के व्यवहार को तय करने में एक प्रमुख कारक उनके आसपास ईरान, इराक और सऊदी अरब की उपस्थिति है।

भी आपस में क्षेत्रीय विवादों में उलझे पड़े हैं। उदाहरण के लिए, बहरीन और कतर के बीच फश्त अल दीबल और कितात जरादाह पर नियंत्रण को लेकर विवाद है और ओमान एवं यमन के बीच खुरिया मुरिया द्वीपों पर विवाद चल रहा है। यह बहुत सहजता के साथ कहा जा सकता है कि ईरान और जीसीसी देशों की विदेश नीति फारस की खाड़ी की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखे बिना तय नहीं की जा सकती। इसी प्रकार, छोटे जीसीसी देशों की विदेश नीति के व्यवहार को तय करने में एक प्रमुख कारक उनके आसपास ईरान, इराक और सऊदी अरब की उपस्थिति है।

अरब की दुनिया का सबसे पुराना आज़ाद मुल्क, ओमान- अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है और इसके उत्तर एवं उत्तर- पूर्व में ओमान सागर और दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व में अरब सागर है। इन जल- निकायों के साथ- साथ सऊदी अरब के रुब अल खाली (खाली मकान) तक अत्याधुनिक साधनों की मदद से भी पहुँच पाना संभव नहीं है, जिसके कारण ओमान अरब प्रायद्वीप के अंदरूनी हिस्सों से अलग- थलग पड़ गया है और संभवतः इसी से एक स्वतंत्र विदेश नीति को आकार देने में मदद मिली। अल हजर पहाड़

अरब की दुनिया का सबसे पुराना आज़ाद मुल्क, ओमान- अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है और इसके उत्तर एवं उत्तर- पूर्व में ओमान सागर और दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व में अरब सागर है।

फारस की खाड़ी से अरब सागर तक फैला ओमान, होर्मुज जलडमरुमध्य की देखरेख करता है, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चेकप्वाइंट्स में से एक है और टैंकर हर दिन लगभग 17 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से ले कर जाते हैं।

रास मुसंदम प्रायद्वीप से लेकर ओमान के पूर्वी छोर पर स्थित सूर शहर तक तट और रेगिस्तान के बीच एक पट्टी बनाते हैं और यह एक अन्य भौगोलिक बाधा है जो ओमान के अंदरूनी इलाकों को विदेशी सैन्य हस्तक्षेप से मुक्त रखती है। इसके अलावा, सऊदी अरब की सीमा और ईरान के साथ होर्मुज जलडमरुमध्य को साझा करने के कारण ओमान दो मजबूत पड़ोसियों की उपस्थिति को समझता है और उसने एक लचीली विदेश नीति बनाए रखी है। हालाँकि, इसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति ने बाहरी-शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है; उदाहरण के लिए, ओमान की खाड़ी के प्रवेश बिंदु के पास मसीराह का बंजर द्वीप, ब्रिटिश और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य सुविधाओं का स्थान बन गया है।[26]

फारस की खाड़ी से अरब सागर तक फैला ओमान, होर्मुज जलडमरुमध्य की देखरेख करता है, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चेकप्वाइंट्स में से एक है और टैंकर हर दिन लगभग 17 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से ले कर जाते हैं। दो तरफ से जल निकायों से घिरे ओमान का समुद्री इतिहास समृद्ध है; इसके समुद्री संबंधों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका में एक समुद्री साम्राज्य की स्थापना की, जो आधुनिक ईरान और पाकिस्तान से मकरान तट, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण- पूर्वी छोर और अफ्रीका के पूर्वी तट के अधिकांश भाग तक फैला हुआ था। ओमान के क्षेत्रीय प्रभाव ने पुर्तगाल और ब्रिटिश साम्राज्य जैसी यूरोपीय औपनिवेशिक ताकतों के साथ संबंधों को भी बढ़ावा दिया।[27] प्राचीन समुद्री इतिहास को नवीनीकृत करते हुए इसने सतर के दशक के प्रारंभ में,

ओमान ने शाही नौसेना की स्थापना की और वर्तमान में यह जहाज निर्माण में अपनी कलात्मकता के लिए जाना जाता है। ओमान के पास खाड़ी और मेडागास्तक द्वीप के बीच इलाके का सबसे बड़ा और वाणिज्यिक बेड़ा था,[28] और ओमान के नाविक अहमद बिन मजीद बिन मोहम्मद अल-सादी, जो नौवहन और समुद्री विज्ञान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति थे, ने, अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी तट को भारत, सीलोन और जावा से जोड़ने वाली समुद्री मार्ग की खोज की थी।[29] एक मजबूत समुद्री शक्ति होने के इतिहास के साथ, ओमान इस क्षेत्र में एक मजबूत ताकत के रूप में उभरा है। अब एक छोटी शक्ति होने के बावजूद, यह सहिष्णुता की इबादी परंपरा को संजोए हुए है और उसे संरक्षित रखता है तथा बहु-संस्कृतिवाद का केंद्र है।

ओमान की विदेश नीति इस तथ्य पर आधारित है कि एक ओर इसकी सीमा सऊदी अरब, यूएई और यमन से लगती है तो वहीं दूसरी ओर होर्मुद जलडमरूमध्य के पार ईरान है। इन देशों के साथ सीमा साझा करने वाले ओमान का सऊदी अरब और यूएई के साथ अल बुरामी ओएसिस (1952-1955) को लेकर क्षेत्रीय विवाद था। ओएसिस में ओमान और आबूधाबी के कबीले रहते थे लेकिन वहाबी धार्मिक आंदोलन के अनुयायियों ने लंब समय तक इस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था और कर वसूलते रहे थे। क्षेत्र में तेल के मिलने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब ने इसे नखलिस्तान पर अपना दावा करने के लिए एक छोटी सेना भेजी। हालाँकि, मध्यस्थता के असफल प्रयासों के बाद और अंग्रेजों द्वारा भेजे गए ओमान के युद्धक स्काउट्स की मदद से एक समझौता हुआ जिसमें

एक मजबूत समुद्री शक्ति होने के इतिहास के साथ, ओमान इस क्षेत्र में एक मजबूत ताकत के रूप में उभरा है। अब एक छोटी शक्ति होने के बावजूद, यह सहिष्णुता की इबादी परंपरा को संजोए हुए है और उसे संरक्षित रखता है तथा बहु-संस्कृतिवाद का केंद्र है।

जातीयता, भाषा और धर्म की दृष्टि से ओमान खाड़ी के सबसे विविधतापूर्ण देशों में से एक है।

सऊदी अरब ने नखलिस्तान पर आबू धाबी और ओमान के दावों को मान्यता दी। इसी तरह, ओमान संघर्ष से जूझ रहे पड़ोसी देश यमन के महत्व को भी समझता है। इससे पहले, ओमान और यमन की सीमा आंशिक रूप से परिभाषित थी लेकिन जब मई 1990 में उत्तर और दक्षिण यमन का विलय हुआ तो, ओमान ने 1992 में नए संयुक्त यमन गणराज्य के साथ अपने सीमा विवादों को सुलझा लिया। इसके अलावा, ओमान के दक्षिणी भाग का मुसन्दम प्रायद्वीप पर स्थित उसके परिक्षेत्र से भौतिक पृथक्करण ओमान और विभिन्न पड़ोसी अमीरातों के बीच टकराव का एक कारण था जो 1971 में संयुक्त अरब अमीरात बन गए। हालाँकि, 1980 में ईरान-इराक युद्ध के शुरू होने के बाद विवादित क्षेत्र पर मतभेद कम हो गए,[30] और 2002 में, मस्कट और आबू धाबी ने इस क्षेत्र एवं संयुक्त अरब अमीरात के शेष हिस्से के बीच अपनी सीमा निर्धारित कर दी।

समाज और जनसांख्यिकी

जातीयता, भाषा और धर्म के मामले में ओमान खाड़ी के सबसे विविधताओं से भरे देशों में से एक है। इसकी जातीय जनसांख्यिकीय संरचना में अरब, बलूची, दक्षिण एशियाई (भारतीय, पाकिस्तानी, श्रीलंकाई और बांग्लादेशी) और अफ्रीकी जातीयताएं शामिल हैं एवं भाषाई संरचना के मामले में, ओमान में अरबी, अंग्रेजी, बलूची, स्वाहिली, उर्दू, मलयालम और बंगाली बोलने वाले लोग रहते हैं। धार्मिक संरचना के संदर्भ में, 2020 के अनुमान के अनुसार ओमान में 85.9 प्रतिशत मुस्लिम, 6.4 प्रतिशत ईसाई, 5.7 हिंदू और 2 प्रतिशत अन्य समुदाय से हैं।[31] ओमान की जातीय, भाषाई और धार्मिक बहुलवाद पर

सहिष्णुता और धैर्य ओमान के समाज की ताकत है जो इसकी विदेश नीति निर्माण में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

अहमद अल इस्माइली के अध्ययन में कहा गया है कि सामूहिक मानसिकता सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देती है, भले ही यह अवधारणा पिछले दशक में ही लोकप्रिय हुई है। ओमान का समाज धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है लेकिन इसमें दूसरी कमियां भी हैं; ओमानी सामूहिक मन गुलामों को स्वतंत्र लोगों से, अरबों को विदेशियों से और बेडौइन को शहरी समुदायों से अलग करता है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि ओमानी समाज बदल रहा है और इसके निहितार्थ राजनीतिक निर्णय लेने में स्पष्ट हैं।[32] इसी तरह, जे. ई. पीटरसन ने अपने लेख में कहा है कि मिश्रित पड़ोस वाले शहरी केंद्र के रूप में मस्कट के विकास ने समुदायों के बीच आपसी मेलज़ोल को बढ़ावा दिया है और सहिष्णुता के स्तर में वृद्धि हुई है।[33] ओमान के समाज और जनसांख्यिकी ने इसकी विदेश नीति निर्माण को प्रभावित किया है; यह देश अन्य देशों की तुलना में प्रवासियों के प्रति अपेक्षाकृत खुला और सहिष्णु है। एचएसबीसी एक्सपैट एक्सप्लोरर सर्वे 2016 के अनुसार, प्रवासी आबादी के लिए सहिष्णुता उप-मानदंड में ओमान चौथे स्थान पर है।[34] सहिष्णुता और धैर्य ओमानी समाज की विशेषताएं हैं जो इसकी विदेश नीति निर्माण में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। जेरेमी जोन्स और निकोलस राइडआउट[35] ने ओमान में विदेश नीति निर्माण के इस पहलू पर विस्तार से चर्चा की है।

हालाँकि, ओमान जनसांख्यिकीय परिवर्तन से गुज़र रहा है; कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के बढ़ते आव्रजन के कारण 1970 के बाद से ओमान में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि में तेज़ी आई है।[36] फरवरी 2023 में, ओमान की कुल आबादी में 57.75 प्रतिशत मूल निवासी थे, जबकि कुल आबादी में 42.26 प्रतिशत प्रवासी थे। 2.1 मिलियन कार्यबल में ओमानी (0.7 मिलियन) के साथ- साथ प्रवासी श्रमिक (1.3 मिलियन)[37] भी हैं जो निजी और

सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और देश को प्रवासी कार्यबल पर प्रतिबंध लगाए बिना अपने मूल नागरिकों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, महामारी के दौरान ओमान की अर्थव्यवस्था में 2.8 प्रतिशत की गिरावट आई,[38] और महामारी के बाद के वर्षों में देश में सुधार की धीमी गति दर्ज की जा रही है; अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2023 में ओमान के लिए 2.7 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि की भविष्यवाणी की है।[39] खाड़ी के अन्य देशों की तरह, ओमान अपनी बढ़ती युवा आबादी के लिए रोज़गार सुनिश्चित करना चाहता है और उसने नौकरियों के ओमानीकरण का सहारा लिया है। साल 2021 में, ओमान ने वित्तीय क्षेत्रों में अपने नागरिकों के लिए कई नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया, जिसमें लेखांकन, लेखा परीक्षा, ब्रोकरेज, बीमा, मुद्रा विनिमय और संपत्ति शामिल हैं।[40]

ओमान ने शाही आदेश 53/2023 के माध्यम से नया श्रम कानून जारी किया है; इससे पहले, ओमान का श्रम क्षेत्र शाही आदेश 35/2003 के माध्यम से जारी कानूनों द्वारा शासित था। नए कानून के अनुसार, रोजगार ओमानियों के लिए एक अंतर्निहित अधिकार है और प्रत्येक प्रतिष्ठान को ओमानी नागरिकों द्वारा गैर- ओमानी श्रमिकों के स्थानीयकरण एवं प्रतिस्थापन के लिए अपनी वार्षिक योजना का खुलासा करना होगा। इसके अलावा, योजना को कार्यस्थल पर और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रतिष्ठान में कार्यरत ओमानी श्रमिकों की कुल संख्या, वेतन संरचना, लिंग संतुलन और नौकरी के अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ओमानी नागरिक कार्यबल पिरामिड के ऊपरी स्तरों पर भी कार्यरत हों, कानून उन्हें एक योजना तैयार करने का निर्देश देता है जिसमें नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए ओमानियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण

खाड़ी के अन्य देशों की तरह, ओमान अपनी बढ़ती युवा आबादी के लिए रोज़गार सुनिश्चित करना चाहता है और उसने नौकरियों के ओमानीकरण का सहारा लिया है।

ओमान की केस स्टडी

चूँकि ओमान में जीसीसी के अन्य देशों की तुलना में मूल आबादी का प्रतिशत अधिक है, इसलिए उन्हें कार्यबल में शामिल करने की चुनौती अधिक है।

को शामिल किया जाए तथा इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। श्रम बल के *ओमानीकरण* को बढ़ावा देने के लिए नया कानून किसी प्रतिष्ठान को किसी गैर-ओमानी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने की अनुमति देता है यदि कोई ओमानी कर्मचारी उसी पद पर उनकी जगह लेने को उपलब्ध हो।[41] साल 2003 के श्रम कानून में उल्लेख किया गया है कि कोई नियोक्ता जनशक्ति मंत्रालय से परमिट प्राप्त करने के बाद किसी विदेशी नागरिक को नियुक्त कर सकता है, और परमिट केवल तभी दिया जाएगा जब उन पदों के लिए ओमान के नागरिक अनुपलब्ध हों। साथ ही, नियोक्ता को *ओमानीकरण* के निर्धारित प्रतिशत का अनुपालन करना होगा।[42] ओमानी कार्यबल के प्रोत्साहन का पालन नहीं करने वाले नियोक्ताओं के लिए दंड का भी प्रावधान है।

चूँकि ओमान में जीसीसी के अन्य देशों की तुलना में मूल आबादी का प्रतिशत अधिक है, इसलिए उन्हें कार्यबल में शामिल करने की चुनौती अधिक है। विज़न 2040 के अनुसार, ओमान का लक्ष्य निजी क्षेत्र में मूल नागरिकों का प्रतिशत 2016 के 11.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 2030 तक 35 प्रतिशत और 2040 तक 40 प्रतिशत करना है।[43] जनवरी 2018, ओमान ने श्रम मंत्रालय के निर्णय संख्या 38/2018 के माध्यम से 87 पदों पर प्रवासी कर्मचारियों को नियुक्त करने पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया। साल 2020 में, ओमान ने घोषणा की कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ केवल ओमान के नागरिकों को ही नौकरी पर रख सकती हैं। जून में, परिवहन मंत्रालय और कृषि एवं मत्स्य मंत्रालय ने डिलीवरी की नौकरियों को केवल अपने नागरिकों के लिए आरक्षित करने हेतु विनियामक उपाय किए। इससे पहले मई में, देश ने घोषणा की थी कि निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक नागरिकों की भर्ती की जाएगी

सप्रू
हाउस
शोधपत्र

खं
ड

और वे सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवासियों की जगह लेंगे।[44] ओमान के श्रम मंत्री ने निर्णय संख्या 235/2022 के माध्यम से 207 व्यवसायों के लिए प्रवासियों को काम पर रखने पर प्रतिबंध की घोषणा की।[45] हाल ही में, ओमान ने महिला प्रवासी श्रमिकों के लिए कार्य वीज़ा देने पर रोक लगाई है।[46] खाड़ी देश को पता है कि ये उपाय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपींस जैसे दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए हानिकारक हैं लेकिन इसने कूटनीति पर घरेलू चिंताओं को प्राथमिकता दी है। अक्टूबर 2017 और 2018 के बीच, ओमानी श्रम बल में प्रवासियों की संख्या में 3.4 प्रतिशत की कमी आई है।[47]

राजनीति

ओमान की सल्तनत की विदेश नीति के लिए राजनीति एक अन्य निर्धारक तत्व है और विदेश मंत्रालय के अनुसार संवाद और सहिष्णुता इसके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। खाड़ी देश इस क्षेत्र में शांति की कल्पना करता है और आर्थिक विकास एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देते हुए, सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संबंधों को मजबूत बनाने के लिए तैयार है। ओमान का नज़रिया ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद की राजनीतिक सोच पर आधारित है जिन्हें आधुनिक ओमान का जनक भी कहा जाता है। संवाद, सहिष्णुता, सुरक्षा और स्थिरता ओमान के लिए कूटनीति के मुख्य शब्द हैं और

ओमान का नज़रिया ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद की राजनीतिक सोच पर आधारित है जिन्हें आधुनिक ओमान का जनक भी कहा जाता है। संवाद, सहिष्णुता, सुरक्षा और स्थिरता ओमान के लिए कूटनीति के मुख्य शब्द हैं और सुल्तान कबूस बिन सैद द्वारा दी गई 50 वर्षों की स्थिरता एवं आर्थिक विकास को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

इसने सऊदी अरब और ईरान जैसे विरोधी राजनीतिक विचारधारा वाले देशों समेत पड़ोस में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे और कई मुद्दों पर तटस्थता अपनाकर एवं क्षेत्र में विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में स्वयं को स्थापित करने में सफल रहा।

सुल्तान कबूस बिन सैद द्वारा दी गई 50 वर्षों की स्थिरता एवं आर्थिक विकास को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

सुल्तान कबूस ने अपने शासन के पांच दशकों तक विदेश मंत्री का पदभार संभाला और अपने उप मंत्रियों सैय्यद फ़हद बिन महमूद अल सैद (1971-1979), क़ैस बिन अब्दुल मुनीम अल ज़वावी (1979-1995) और यूसुफ़ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला (1997-2020) की मदद से नीतियां बनाईं। उनके उत्तराधिकारी, हैथम बिन तारिक अल सैद वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी, राजनीतिक मामलों के अवर सचिव शेख खलीफ़ा अल हर्थी और प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों के अवर सचिव खालिद अल मुसलाही के साथ विदेश संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। सुल्तान कबूस, जिन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई की है, ने, ओमान के आधुनिकीकरण पर ज़ोर दिया और मूलभूत सुविधाओं के विकास, ओमान के पहले संविधान की घोषणा, ओमानी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करने और अरब लीग एवं संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता प्राप्त करने एवं जीसीसी के संस्थापक सदस्य बन कर पड़ोस में ओमान के अलगाव को समाप्त करने संबंधी कई परियोजनाओं का नेतृत्व किया। इसने सऊदी अरब और ईरान जैसे विरोधी राजनीतिक विचारधारा वाले देशों समेत पड़ोस में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे और कई मुद्दों पर तटस्थता अपनाकर एवं क्षेत्र में विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में स्वयं को स्थापित करने में सफल रहा।

सुल्तान कबूस ने अपने उप मंत्रियों सैय्यद फ़हाद, कैस अल ज़वावी और यूसुफ़ बिन अलावी की मदद से दूसरे देशों के साथ ओमान के संबंध को निर्देशित किया और यह उनकी विदेश नीति निर्माण में स्पष्ट था।

जेफरी ए लेफेब्रे का तर्क है कि वर्तमान में ओमान स्वतंत्रता, व्यावहारिकता और संयम की विशेषता वाली नीति का अनुसरण करता है और यह तब से आकार लेना शुरू हो गया था जब से सुल्तान काबूस ने अपने पिता सैद बिन तैमूर के जुलाई 1970 में मस्कट में महल के तख्तापलट के बाद शासन संभाला।[48] उन्होंने यह भी कहा कि ओमान की व्यावहारिक विदेश नीति का आधार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक महान शक्ति संरक्षक के रूप में इसके संरेखण और दुश्मन बनाने से बचना है; इसका तात्पर्य यह है कि ओमान की विकसित विदेश नीति इसके रणनीतिक स्थान, तेल-पश्चात अर्थव्यवस्था पर ध्यान और रूढ़िवाद एवं सहिष्णुता की इबादी संस्कृति समेत कारकों पर आधारित है। एक और मुद्दा जो उन्होंने उठाया वह ओमान की विदेश नीति में दीर्घकालिक दिशा की अनुपस्थिति के बारे में है; हालाँकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि ओमान की विदेश नीति की नींव सुल्तान कबूस ने रखी थी जिन्होंने इसे पोषित किया और आधी सदी तक इसे दिशा दिया एवं कार्यशील बनाए रखा। ओमान की विदेश नीति का भविष्य सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सैद की इस क्षमता पर निर्भर करेगा कि वह सुल्तान कबूस द्वारा तैयार दिशानिर्देशों या मुख्य बिंदुओं से विचलित हुए बिना बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक गतिशीलता के अनुसार स्वयं को ढाल सकें।

सुल्तान कबूस ने अपने उप मंत्रियों सैय्यद फ़हाद, कैस अल ज़वावी और यूसुफ़ बिन अलावी की मदद से दूसरे देशों के साथ ओमान के संबंध को निर्देशित किया और यह उनकी विदेश नीति निर्माण में स्पष्ट था। उनके पहले उप मंत्री, सैय्यद फ़हाद, ने फ्रांसीसी महिला से विवाह किया था और आधुनिक- पाश्चात्य मूल्यों की उन्हें जानकारी थी, जबकि उनके दूसरे उप मंत्री, कैस अल ज़वावी, ज़वावी समूह के संस्थापक हैं और उनकी पढ़ाई- लिखाई बॉम्बे में हुई थी। यह संभावना है कि उन्होंने भारत में प्रचलित

सहिष्णुता की भावना को आत्मसात किया है। ज़वावी ओमान के आधुनिकीकरण और पुनर्जागरण की शक्ति में विश्वास करते थे और ओमान के लिए नए दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु अथक प्रयास करते थे। उन्होंने एक नई अर्थव्यवस्था की गतिशीलता की भी सराहना की और विकासशील ओमान के लिए व्यवसायों का एक विविध केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा।[49] सुल्तान कबूस के तीसरे उप- मंत्री, यूसुफ़ बिन अलावी, साम्यवादी झुकाव वाले थे जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सुल्तान अपने नज़रिए में समावेशी थे। यूसुफ़ बिन अलावी के साथ सिगर्ड न्यूबॉयर का साक्षात्कार उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है जो उनके विनम्र मूल, गमाल अब्देल नासर के सर्व-अरब मूल्यों के लिए प्रशंसा और मुहम्मद हुसैन हयाकल के साप्ताहिक स्तंभ से प्रेरित था। उनका सलालाह के समाजवादी नेताओं से संपर्क था और उन्होंने ढोफर विद्रोह (1963-1976) में भी हिस्सा लिया था। आगे चल कर, उन्होंने आधुनिक ओमान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[50]

अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किसी देश की भूमिका के लिए विदेश नीति महत्वपूर्ण है लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी देश की आर्थिक स्थितियाँ और क्षमताएं उसके घरेलू और विदेशी संबंधों के निर्णायक कारक होती हैं। उदाहरण के लिए, जब सुल्तान कबूस के पिता सुल्तान सैद बिन तैमूर ने 1932 में सत्ता संभाली, तो ओमान की अर्थव्यवस्था कई कारणों से खराब स्थिति में थी, जिसमें भाप के जहाजों के आविष्कार के बाद ओमान की नौसैनिक शक्ति में गिरावट, निर्यात हेतु सीमित वस्तुएं और ज़ांज़ीबार द्वारा सब्सिडी का अनियमित भुगतान शामिल था।[51] परिणामस्वरूप, दो दशकों के बाद, सुल्तान सैद बिन तैमूर ने ब्रिटेन से मदद मांगी, जिसने सुल्तान की सशस्त्र सेनाओं, नागरिक उड्डयन, रॉयल एयर फोर्स सुविधाओं और ओमान में आर्थिक विकास के निर्माण में ओमान की मदद की। इस अवधि

वर्तमान सुल्तान हैथम बिन तारिक ने कहा कि ओमान का विज़न 2040 प्रभावी आर्थिक प्रबंधन सुनिश्चित करने और एक विकसित, विविध और दीर्घकालिक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक, निजी एवं नागरिक क्षेत्रों के कार्यों को नया रूप देने पर केंद्रित है।

के दौरान ओमान ने जिन अन्य देशों के साथ संधियाँ कीं, वे थे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस।

वर्ष 1962 में हाइड्रोकार्बन की खोज ने देश के शुरुआती वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया और सुल्तान कबूस के कुशल नेतृत्व में, ओमान की अर्थव्यवस्था विस्तार (1970-1986), छंटनी (1986-1989) और स्थिरीकरण (1990 के बाद) के चरणों से गुजरी। देश सबसे गरीब अरब राज्य से मध्यम आय वाले अरब देश में बदलने में सक्षम रहा है। सुल्तान के आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों ने सड़कों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, कम लागत वाले घरों, गहरे पानी के बंदरगाह, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बिजली उत्पादन संयंत्रों और विलवणीकरण संयंत्रों के रूप में बेहद जरूरी मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से ओमान के विकास को बढ़ावा दिया है। देर से प्रवेश करने के बावजूद, ओमान के विकास को हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न तेल राजस्व द्वारा वित्त पोषित किया गया था; हालाँकि घटते संसाधनों के मद्देनज़र, देश अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता ला रहा है।[52]

वर्ष 1962 में सल्तनत में तेल की खोज से पहले ओमान की अर्थव्यवस्था कृषि, मछली पालन और व्यापार पर आधारित थी। वर्तमान में ओमान तेल उत्पादन के लिहाज़ से विश्व में 21वें स्थान पर है और तेल की खपत की लिहाज़ से 57वें स्थान पर। साल 2020 में ओमान के सकल घरेलू उत्पाद में हाइड्रोकार्बन का योगदान 26.2 प्रतिशत था। ओमान के ऊर्जा और खनिज मंत्रालय के अनुसार, जून 2022 में खाड़ी देश के पास 5.2 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार और

24 ट्रिलियन क्यूबिक फीस गैस का भंडार था[53], इसी साल ओमान ने नए तेल क्षेत्रों की खोज की जो अगले 2-3 वर्षों में इसके तेल के उत्पादन को 50,000 से 100,000 बैरल तक बढ़ा देंगे।[54] हालाँकि, ओमान मूल रूप से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक/OPEC) का हिस्सा नहीं था लेकिन 2017 में यह ओपेक+ (OPEC+) में शामिल हो गया। वर्तमान सुल्तान हैथम बिन तारिक ने कहा कि ओमान का विज़न 2040 प्रभावी आर्थिक प्रबंधन सुनिश्चित करने और एक विकसित, विविध और दीर्घकालिक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक, निजी एवं नागरिक क्षेत्रों के कार्यों को नया रूप देने पर केंद्रित है।[55]

हाल के दशकों में, ओमान ने अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा निर्भरता में विविधता लाई है और नवीकरणीय ऊर्जा पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है। यह 2030 तक 30 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना चाहता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश ने कई परियोजनाओं पर काम शुरू किया है, जिसमें ढोफ़र में एक पवन फार्म, मनाह में दो सौर स्वतंत्र बिजली परियोजनाएं और देश में 11 सौर- डीज़ल हाइब्रिड सुविधाएं शामिल हैं।[56] वर्ष 2015 में, ओमान के सरकारी स्वामित्व वाले पेट्रोलियम डेवलपमेंट ने दुनिया के सबसे बड़ो सौर संयंत्रों में से एक, ग्लास प्वाइंट मीराह, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, के लिए 7- मेगावाट (MW) की पायलट परियोजना शुरू की। ओमान ने अपना पहला अपशिष्ट- से- ऊर्जा (WtE) संयंत्र शुरू किया है जिसकी क्षमता प्रतिदिन 4500 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का उपचार करने, 130-150 मेगावाट घंटे की विद्युत उत्पादन क्षमता उत्पन्न करने तथा लैंडफिल से 80 प्रतिशत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को हटाकर विज़न 2040 का समर्थन करने की है।[57]

नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान बढ़ाने के अपने प्रयास में ओमान चीन, जापान, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों के साथ सहयोग कर रहा है।

ओमान इस बात को समझता है कि अन्य देशों में निवेश करने से विदेशी संबंध मजूबत बनते हैं, और इसलिए वह क्षेत्र में और उसके बाहर आर्थिक कूटनीति अपनाता है।

नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी इच्छा में, ओमान चीन, जापान, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों के साथ मिल कर काम कर रहा है। इसने 1994 से जीसीसी देशों को स्वतंत्र जल एवं बिजली संयंत्रों की ओर अग्रसर किया है। ओमान का लक्ष्य 2040 तक हाइड्रोजन-केंद्रित अर्थव्यवस्था बनाना है और हैथम सरकार ने कई हरित हाईड्रोजन परियोजनाओं की घोषणा की है जिसमें 25गीगावाट (GW) पनव और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित 14 गीगावाट (GW) की सुविधा शामिल है। मिडल ईस्ट इकॉनमिक डाइजेस्ट (एमईईडी/MEED) के अनुसार, ओमान ने 45 बिलियन अमेरिका डॉलर से अधिक की हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजनाओं की योजना बनाई है। खाड़ी देश ने हाइड्रोजन परियोजनाओं के प्रबंधन हेतु ऊर्जा और खनिज मंत्रालय में स्वच्छ ऊर्जा और हाइड्रोजन के लिए एक महानिदेशालय एवं हाइड्रोजन डेवलपमेंट ओमान नाम की एक सहायक कंपनी की भी स्थापना की है।[58]

ओमान समझता है कि दूसरे देशों में निवेश करने से दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होते हैं और इस उद्देश्य से वह ओमान में और उसके बाहर आर्थिक कूटनीति का अनुसरण करता है। दिसंबर 2022 में ओमान का विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश 944.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ चुका था।[59] ओमान दूसरे देशों में निवेश भी कर रहा है; जैसे, ओमान की परियोजना वित्तपोषण निधि, अनवर एशियन इन्वेस्टमेंट्स ने बंदरगाह शहर ग्वादर को पाकिस्तान की मुख्य रेलवे प्रणाली से जोड़ने वाली रेल लाइन के वित्तपोषण में दिलचस्पी दिखाई है।[60] ओमान ने ओमान ऑयल कंपनी के माध्यम से हंबनटोटा बंदरगाह पर श्रीलंका तेल रिफाइनरी परियोजना में निवेश करने में भी दिलचस्पी दिखाई है।[61]

ओमान के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने 2022 में एक द्विपक्षीय परामर्श बैठक में उल्लेख किया कि ओमान बांग्लादेश में निवेश करने में रुचि रखता है और इस बात की संभावना है कि खाड़ी देश खाद्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, हाई-टेक पार्क, जहाज निर्माण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश करेगा।[62]

जून 2023 में, मस्कट ने ढाका के साथ 10- वर्षों का गैस निर्यात समझौता किया था।[63] ओमान अफ्रीकी देशों में अपने निवेश को बढ़ा रहा है; ओमान निवेश प्राधिकरण ने रसद, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन में निवेश एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए तंजानियाई समकक्षों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू/ MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह ओमान ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने अफ्रीका में तेल और स्नेहक उत्पादों की बिक्री स्थापित करने के लिए एलेक्जेंड्रिया पेट्रोलियम एडिटिव्स और मिस्र पेट्रोलियम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।[64] ओमान के लिए सीरिया के उद्योग और सीमेंट विनिर्माण क्षेत्रों में[65] और नेपाल के जल-विद्युत, कृषि, मूलभूत सुविधाओं एवं उद्योग क्षेत्रों में निवेश करने का भी अवसर है।[66]

आर्थिक कूटनीति का एक और आयाम ओमान में निवेश की तलाश करते हुए मधुर संबंधों को आगे बढ़ाना है। देश ने इटली और स्विट्ज़रलैंड से ग्रीन हाइड्रोजन,[67] और मलेशिया से हलाल खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, पर्यटन और तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश की मांग की है।[68] ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ़ ने कहा कि देश का लक्ष्य आर्थिक प्रोत्साहन योजना और निवेश एवं निर्यात विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम "नेज्दाहर" के माध्यम से ओमान सल्तनत में गुणवत्तापूर्ण निवेश आकर्षित

आर्थिक कूटनीति का एक और आयाम ओमान में निवेश की तलाश करते हुए मधुर संबंधों को आगे बढ़ाना है।

यूनाइटेड किंग्डम ओमान में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है।

करना है। कार्यक्रम स्थानीय और विदेशी निवेश के माहौल का मूल्यांकन करता है, चुनौतियों का विश्लेषण करता है और उन्हें सुधारने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाता है। साल 2022 में, ओमान और यूनाइटेड किंग्डम (UK) मे अपने आर्थिक संबंधों में बेहतर करने और स्वच्छ ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी में उच्च- मूल्य निवेश को बढ़ाने के लिए एक संप्रभु निवेश भागीदारी (एसआईपी) बनाई थी। [69] यूनाइटेड किंग्डम ओमान में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। ओमान ने अनुकूल घरेलू निवेश माहौल को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं; इसने दुक़म, अल मज़ुना फ्री ज़ोन, सलालाह फ्री ज़ोन और सोहर फ्री ज़ोन में विशेष आर्थिक जोन में निवेश की देखरेख एवं सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों और मुक्त क्षेत्रों (ओपीएजेड/ OPAZ) के लिए लोक प्राधिकरण बनाया है। इसने देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पांच कानून लागू किए हैं जिनमें सार्वजनिक- निजी भागीदारी कानून, विदेशी पूंजी निवेश कानून (एफसीआईएल/ FCIL), निजीकरण कानून, दिवालियापन कानून और वाणिज्यिक कंपनी कानून शामिल हैं।[70]

सुरक्षा और सहायता

सुरक्षा और सहायता ओमान में विदेश नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, जिसके पास इस क्षेत्र में सबसे अच्छे प्रशिक्षित रक्षा बलों में से एक है[71] और 2020 में दुनिया में सबसे अधिक रक्षा बजट (11 प्रतिशत) ओमान का ही था।[72] ओमान के लिए प्रमुख हथियार निर्यातक पोलैंड, अमेरिका और दक्षिण कोरिया हैं, जबकि यह तुर्की से हथियारों की तीन सबसे बड़े आयातकों में से एक है, जो 2022 में इसके कुल निर्यात का लगभग 13

सुरक्षा और सहायता ओमान में विदेश नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, जिसके पास इस क्षेत्र में सबसे अच्छे प्रशिक्षित रक्षा बलों में से एक है और 2020 में दुनिया में सबसे अधिक रक्षा बजट (11 प्रतिशत) ओमान का ही था।

प्रतिशत है।[73] सुल्तान हैथम बिन तारिक ओमान के रक्षा साझेदारों के विविधीकरण और भारत जैसे देशों के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अलावा, ब्रिटेन ओमान के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है। दोनों देशों के बीच 200 साल पुराना ऐतिहासिक संबंध है जब 1798 में एंग्लो-ओमानी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।

ओमान में ब्रिटेन की मुख्य दिलचस्पी दासों के व्यापार की रोकथाम थी, लेकिन इसने धीरे-धीरे खाड़ी देश में अपना प्रभाव बढ़ाया। 1895 के विद्रोह के बाद (ब्रिटिश) भारतीय सेना की टुकड़ियाँ 1913 से 1921 तक राजधानी क्षेत्र की रक्षा के लिए तैनात की गईं और आगे चलकर, ब्रिटेन ने मस्कट में एक राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया जिसे 1947 भारत के आज़ाद होने के एक साल बाद राष्ट्रमंडल कार्यालय के अधीन रखा गया।[74] ओमान में ब्रिटिश प्रभाव अपने चरण पर तैमूर इब्न फ़ैसल अल सैद (1913-1932) के शासनकाल के दौरान पहुँचा था। ओमान के साथ संबंध रखने वाले अन्य देश अमेरिका, फ्रांस और नीदरलैंड थे लेकिन ब्रिटेन के साथ संबंध अभी भी मजबूत हैं। दुकम में ब्रिटिश संयुक्त रसद सहायता बेस 2017 में खोला गया और यूके के रक्षा सचिव गेविन विलियमसन ने घोषणा की कि 2019 में ओमान में एक नया संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम सुचारू और चुस्त संचालन सुनिश्चित करने के लिए दुकम बंदरगाह के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। यूके और ओमान का लक्ष्य सैन्य अभ्यास सैफ सरिया 3 से अपने संयुक्त सीखने के आधार पर एक विश्व स्तरीय सैन्य बल का निर्माण करना है।

जीसीसी के अन्य सदस्य देशों की तरह, ओमान भी समझता है कि सहायता करना देश के भीतर और बाहर अच्छे संबंध बनाए रखने के तरीकों में से एक है।

जीसीसी के अन्य सदस्य देशों की तरह, ओमान भी समझता है कि सहायता करना देश के भीतर और बाहर अच्छे संबंध बनाए रखने के तरीकों में से एक है। हाल ही में, नवंबर 2023 में, इसने गाज़ा पट्टी में फिलिस्तीनियों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की।[75] ओमान ने मार्च 2023 में यमन को मानवीय सहायता देने का वादा किया है[76] और सितंबर 2023 में लीबिया को 80 टन बाढ़ राहत सामग्री भेजी थी।[77] इसके साथ ही ओमान ने लेबनान को लगभग 20 टन जीवन रक्षक दवाइयां भी भेजीं।[78] इसने 2012 में सोमालिया में अकाल के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए राहत दल और 1000 टन से अधिक चिकित्सा सहायता भी भेजी थी।[79] ओमान ने 2022 की विनाशकारी बाढ़ के बाद ओमान की रॉयल नेवी के सैन्य परिवहन जहाजों के माध्यम से पाकिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान की।[80] खाड़ी देश ने फरवरी 2023 में आए भूकंप के मद्देनज़र सीरिया में राहत और चिकित्सा मदद पहुंचाने के लिए एक हवाई पुल बनाने की योजना की भी घोषणा की है।[81] ओमान ने सितंबर 2023 में अफ्रीकी राष्ट्र में आए विनाशकारी भूकंप के प्रभावों से निपटने में मोरक्को के प्रयासों के समर्थन में बचाव दल और तत्काल राहत भेजने के शाही आदेश जारी किए।[82] कुल मिलाकर, 2023 में, ओमान ने आपदाओं और उथल-पुथल से प्रभावित देशों को राहत सामग्री, चिकित्सा प्रावधानों एवं मिश्रित खाद्यपदार्थों समेत 975 टन से अधिक की मदद भेजी।[83]

दुनिया के लोग देखते हैं कि कौन सा देश संकट के समय आगे आता है और कौन सा नहीं। जो देश सबसे ज्यादा परोपकारी माने जाते हैं, उन्हें सबसे अधिक लाभ होता है।

नाओमी लेइट के अनुसार, सहायता का वितरण अलग- अलग देशों की सार्वजनिक कूटनीति रणनीतियों का एक प्रमुख घटक रहा है। सहायता कूटनीति आर्थिक क्षमता के अधार पर कठोर शक्ति का उदाहरण है, लेकिन वास्तव में, यह सार्वजनिक कूटनीति का शक्ति-बढ़ाने वाला अरक्षित उपकरण है। दुनिया के लोग देखते हैं कि संकट के समय कौन से देश आगे आते हैं और कौन से देश अनुपस्थित रहते हैं। जिन देशों को सबसे ज्यादा परोपकारी माना जाता है उन्हें सबसे अधिक लाभ होता है।[84] सहायता प्रदाता होने के साथ- साथ ओमान को कई देशों से सहायता भी मिल रही है। साल 2020 में कतर से उसे 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद मिली थी क्योंकि वह कोरोनावायरस और तेल की कीमतों में कमी से बिगड़े आर्थिक संकट से बचने की कोशिश कर रहा था।[85] वर्ष 2021 में ओमान को अंतरराष्ट्रीय सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण मदद के लिए 1.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आतंकवाद विरोधी मदद के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता संयुक्त राज्य अमेरिका से मिली थी।[86] ओमान के छोटे व्यवसायों को देश के विकास बैंक और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के बीच हस्ताक्षरित 53.33 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त समझौते से लाभ मिलने वाला है। साल 2017 में, ओमान को मूलभूत सुविधाओं एवं औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश करनेक लिए चीन से 3.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मिला था।[87]

क्षेत्रीय माहौल

ओमान की विदेश नीति का निर्माण क्षेत्रीय माहौल एवं पड़ोसी देशों के दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। फारस की खाड़ी में ईरान के प्रभुत्व का मुकाबला करने और विशेष रूप से 1979 की इस्लामी क्रांति के प्रभाव और संभावित डोमिनो प्रभाव को सीमित करने के लिए ओमान ने सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन और कतर के अन्य पांच खाड़ी देशों के साथ मिलकर खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी/ GCC) की स्थापना की। ओमान के जीसीसी के साथ संबंध, कभी- कभार होने वाली परेशानियों को छोड़ दें तो, अच्छे ही रहे हैं; मस्कट की स्वतंत्र विदेश नीति सऊदी नेतृत्व वाली परिषद में परेशानी का सबब रही है।

ओमान की ईरान को अस्तित्व के लिए खतरा मानने के बजाए एक सख्त लेकिन महत्वपूर्ण पड़ोसी के रूप में देखने की धारणा ने क्षेत्र के प्रति उसकी नीतियों को प्रभावित किया है।

ओमान ने 2006 में जीसीसी मौद्रिक संघ को छोड़ दिया, उसके बाद 2009 में यूएई ने भी ऐसा ही किया।[88] जॉर्जियो कैफ़िएरो और एडम येफ़ेट ने उल्लेख किया है कि 2016 में, जीसीसी में ओमान की सदस्यता के भविष्य के बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं। ओमान शूरा परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष इशाक अल सियाबी ने 2016 में संकेत दिया था कि ओमान ब्रेक्सिट जैसा मतदान या ओएक्सआईटी (OXIT) का आयोजन करेगा ताकि जीसीसी में ओमान का भविष्य निर्धारित किया जा सके, क्योंकि परिषद विभिन्न मुद्दों पर सदस्यों के बीच मतभेदों के कारण ऐसा करने में सक्षम नहीं रही है।[89] ओमान ने जल्द ही उस बयान को वापस ले लिया और घोषणा की कि जीसीसी एकीकृत प्रक्रियाओं एवं लंबी अवधि के लिए संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ज रहा है। वर्ष 2013 में, ओमान ने जीसीसी को एक संघ में अपग्रेड करने के सऊदी की मांग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। ओएक्सआईटी के लिए अटकलें निराधार नहीं थीं क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों पर ओमान का अलग- अलग रुख और सक्रिए मध्यस्थता के प्रयास सऊदी अरब के लिए परेशानी का कारण रहे हैं। सुल्तान कबूस की विशाल छवि, जिन्हें पूरे क्षेत्र में सम्मान प्राप्त था, ने, मतभेदों को नियंत्रण में रखा है लेकिन सुल्तान हैथम बिन तारिक के अधीन ओमान के बारे में यही बात निश्चितता के साथ नहीं कही जा सकती।

ओमान की ईरान को अस्तित्व के लिए खतरा मानने के बजाय एक मुश्किल लेकिन महत्वपूर्ण पड़ोसी के रूप में देखने की धारणा ने इस क्षेत्र के लिए उसकी नीतियों को प्रभावित किया है। ईरान के प्रति उसका दृष्टिकोण अन्य देशों की तरह कठोर या तीव्र नहीं है। उसका मानना है कि ईरान से निपटने के लिए आक्रामकता और शत्रुता की तुलना में संवाद और कूटनीति बेहतर एवं अधिक कुशल साधन हैं। ओमान ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि किसी खास देश का साथ देने से जोखिम जुड़े हैं और उसने अपनी विदेश नीति को उसी के अनुसार आकार दिया। तटस्थता उसकी विदेश नीति की एक परिभाषित विशेषता है,

और यह ईरान- इराक युद्ध पर उसके रुख से स्पष्ट था। इसी तरह, जब तक राष्ट्रीय हितों को ख़तरा न हो, तब तक मधुर संबंध बनाए रखना ओमान की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ओमान ने अरब स्प्रिंग[90] के बाद न तो सीरिया के साथ अपने संबंध समाप्त किए और न ही यमन में सऊदी नेतृत्व वाले ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म का हिस्सा बना।[91] क़तर और यूएई के विपरीत, इसने लीबिया संकट में भी हस्तक्षेप नहीं किया बल्कि युद्धरत गुटों के बीच वार्ता आयोजित की तथा अरब लीग के माध्यम से हस्तक्षेप का आह्वान किया।[92] सुल्तान कबूस के नेतृत्व में ओमान ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि क्षेत्रीय भू-राजनीति से प्रभावित होने की निरर्थकता है और उसने विदेश नीति में बीच का रास्ता अपनाने से बचने का जोखिम उठाया है। साल 2017 में कतर ने अलग- थलग करने वाले सऊदी रब, यूएई, बहरीन और मिस्र की चौकड़ी में ओमान शामिल नहीं हुआ और इसके बजाय द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश पर दोहा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।[93]

अंतरराष्ट्रीय माहौल

फ़ारस की खाड़ी में स्थित होने के बावजूद, ओमान अपने पड़ोसी देशों की संवेदनाओं को साझा नहीं करता है। इसके बजाय, इसने दक्षिण एशिया के देशों के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं जो ब्रिटिश उपनिवेश थे। इसने पुर्तगालियों के हाथों अत्याचार झेले थे और छह दशकों (1891-1951) से अधिक समय तक ब्रिटिश संरक्षित देश था। यह ब्रिटेन में विवाद का मुद्दा भी बन गया था जिसने पूर्वी अफ्रीकी दासों के व्यापार पर आपत्ति जताई थी और फ्रांस, जिसने 1844 की संधि के माध्यम से ओमान के लिए 'सबसे पसंदीदा देश' का दर्जा प्राप्त किया था। आज़ाद होने के बाद भी ओमान पर ब्रिटेन का व्यापक प्रभाव था और सुल्तान कबूस को ढोफ़र विद्रोह को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सैन्य सहायता की जरूरत का पूरा अंदाज़ा था। नतीजतन, उन्होंने ब्रिटेन के साथ एक घनिष्ठ सैन्य संबंध को मंजूरी दी

और ओमान में आकर्षक अनुबंधों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को रियायतें भी प्रदान कीं। बाद में, ब्रिटेन ने ओमान को अपने सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण करने और अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया। ओमान- यूके सैन्य संबंध लंबे समय तक मजबूत रहे लेकिन ओमानीकरण की प्रक्रिया के कारण वे कमज़ोर पड़ने लगे। ब्रिटिश जनरल सर टिमोथी क्रीसी, ब्रिटिश थल- सेना के पूर्व कमांडर, 1980 के दशक में दो साल के लिए सेना प्रमुख बनाए गए थे।

सुल्तान कबूस अंतरराष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और समझते थे कि कार्यात्मक संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह सबक आने वाले वर्षों में अन्य देशों के लिए भी प्रासंगिक रहा। ओमान अधिकांश देशों के साथ कार्यात्मक संबंध बनाए रखता है, यदि कोई विवाद होता है, तो उसे नाज़ुक तरीके से संभालता है। यह तथ्य है कि फ्रांस ने ईरान के शाह के कहने पर ओमान की नौसैनिक शक्ति को कम करने से इनकार कर दिया, मस्कट और पेरिस के बीच अच्छे द्विपक्षीय संबंधों का आधार बना। इसी तरह, 1833 की शुरुआत में ओमान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, 1979 में ईरान में शाह के पतन के बाद ओमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों ने गति पकड़ी और ब्रिटेन पर अपनी निर्भरता में विविधता लाने की चाह में, सुल्तान कबूस ने मुसंदम प्रायद्वीप और अल बुरामी ओएसिस में विकास परियोजनाओं का प्रबंधन करने हेतु अमेरिकी कर्मियों को अनुमति प्रदान कर दी। इससे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1972 में ओमान में अपना दूतावास खोला था, और मस्कट ने 1973 में वाशिंगटन में अपना दूतावास खोला था। ओमान ने मिस्र और इज़रायल द्वारा हस्ताक्षरित अमेरिकी नेतृत्व वाली शांति पहल, कैंप डेविड समझौते का समर्थन किया था। सुविधाओं तक पहुँच समझौते (फसिलिटीज़ एक्सेस अग्रीमेंट) ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ओमान को एक साथ लाया और सिब, थमारित और मसीराह में हवाई अड्डों को अमेरिकी सहायता एवं कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ उन्नत किया गया। ओमान में आर्थिक सहायता के वित्त पोषण और प्रशासन हेतु 1980 में संयुक्त अमेरिकी- ओमान आयोग की

स्थापना की गई थी।[94] सुल्तान कबूस के लिए, बहुआयामी खतरों का सामना कर रहे रूढ़ीवादी अरब खाड़ी राजतंत्रों की सुरक्षा के लिए सैन्य सहायता की आवश्यकता थी, जिसे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही प्रदान करने में सक्षम और इच्छुक था।[95] 1980 के दशक में, अमेरिका- ओमान संबंध और बेहतर हो गए क्योंकि दोनों देशों के नेताओं की कई यात्राएं हुई और बातचीत राजनीतिक- सैन्य मुद्दों के इर्द- गिर्द घूमती रही। अक्टूबर 1983 में बेरूत में अमेरिकी सैनिकों पर कार बम विस्फोट के जवाब में, सुल्तान कबूस ने क्षेत्र में शांति वार्ता के लिए एक मॉडल के रूप में कैंप डेविड समझौते के नवीनीकरण का आह्वान किया।[96] संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ओमान का महत्व इस तथ्य से पता लगाया जा सकता है कि कुछ समय के लिए वाशिंगटन ने इसे मिस्र और सऊदी अरब का विकल्प माना था।[97] वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका और ओमान के बीच मित्रता एवं संबंध द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के साथ जारी हैं, जिस पर 2006 में हस्ताक्षर किए गए थे और जिसे 2009 में लागू किया गया था, जिससे दोनों देशों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिला। वर्ष 2016 में, संयुक्त राज्य अमेरिका और ओमान ने द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाते हुए यूएस- ओमान साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए।[98] वर्ष 2019 में,

ओमान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक रणनीतिक रूपरेखा समझौता (स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिकी सेनाओं को अल दुक्म और सलालाह बंदरगाहों का प्रयोग करने की अनुमति देकर अमेरिका- ओमान सुविधा पहुँच समझौते का विस्तार किया गया।[99]

ओमान के यूएसएसआर के साथ दीर्घकालिक संबंध नहीं बन पाए क्योंकि ब्रिटेन ने इसे राजशाही विरोधी बताकर सक्रिए रूप से हतोत्साहित किया। इसके बावजूद, इमामेट और विद्रोहियों को यूएसएसआर पर भरोसा था, उन्हें उम्मीद थी कि ओमान में 1957- 1959 के इमामेट विद्रोह के दौरान उन्हें समर्थन मिलेगा। ढोफ़र विद्रोह के दौरान, यूएसएसआर ने विद्रोहियों के नेतृत्व वाले ढोफ़र लिबरेशन फ्रंट का समर्थन किया और उसे आशा थी कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को उखाड़ फेंकेंगे। आगे चल कर, यह महसूस करते हुए

कि विद्रोह असफल होने वाला था, सोवियत संघ ने कहा कि विद्रोह स्थानीय कारणों से शुरू हुआ था और इसका विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन से कोई लेना- देना नहीं था। ओमान और पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन (पीडीआरवाई/ PDRY), जो 1967 से 1990 तक इस क्षेत्र का एकमात्र साम्यवादी देश था, ने, कुवैत के समर्थन से 1982 में अपने संबंधों को सामान्य कर लिया, जिसके बाद यूएसएसआर का सुल्तान कबूस के प्रति रवैया नरम पड़ा। इसने ओमान को पश्चिमी साम्राज्यवाद का शिकार समझना शुरू कर दिया। वर्ष 1985 में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचेव के सत्ता में आने के साथ ही सोवियत विदेश नीति अपनी वैचारिक प्रवृत्तियों से हट गई और व्यावहारिकता एवं आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने लगी। इसी परिदृश्य में, ओमान ने जॉर्डन की मदद से सितंबर 1985 में यूएसएसआर के साथ संबंध स्थापित किए। सुल्तान कबूस के निर्णय को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्यता, पूर्व और पश्चिम के बीच संतुलन और पीडीआरवाई को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता जैसे विचारों पर आधारित माना जाता था। लेकिन दोनों देशों को एक साथ बांधने वाले सामान्य मुद्दे थे फिलीस्तीन के प्रश्न का शांतिपूर्ण समाधान, ईरान- इराक युद्ध के दुष्परिणाम और हिंद महासागर का सैन्यीकरण। यूएसएसआर ने पीडीआरवाई के साथ सीमा मुद्दे के बातचीत के जरिए समाधान का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई क्योंकि वह मध्य एशिया में ईरानी क्रांति के प्रभावों से चिंतित था। सोवियत संघ के बाद के दौर में, रूस ने बीटीआर 80 बख्तरबंद कार्मिक वाहक और अन्य आर्थिक अनुबंधों की बिक्री के माध्यम से ओमान को दुर्लभ मुद्रा (हार्ड करेंसी) प्राप्त करने के रूप में देखा। वर्तमान में, रूस- ओमान संबंध व्यापार संबंधों को बढ़ाने, सक्रिए राजनीतिक संवाद बनाए रखने, अंतर- संसदीय संपर्कों को मजबूत करने, प्रतिनिधिमंडलों का आदान- प्रदान करने और दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। वर्ष 2023 में मास्को की यात्रा के दौरान, ओमान के विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष के साथ यमन,

रूस इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि फ़ारस की खाड़ी में सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को आकार देने के लिए ओमान को अब जीसीसी की अध्यक्षता सौंपी जानी चाहिए।

सीरिया और मध्य- पूर्व निपटान प्रक्रिया समेत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। रूस इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि फ़ारस की खाड़ी में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को आकार देने के लिए अब ओमान को जीसीसी की अध्यक्षता करनी चाहिए। जुलाई 2023 में मास्को में आयोजित रूस-जीसीसी रणनीतिक वार्ता की छठी मंत्रिस्तरीय बैठक में यह चर्चा का प्रमुख मुद्दा बना।[100]

ओमान का चीन के साथ ऐतिहासिक संबंध 8वीं शताब्दी से है, जिसमें ओमानी व्यापारियों के चीन आने और ओमानी वाणिज्यिक जबाजों के नियमित अंतराल पर ग्वांगझू में रुकने का विवरण है।[101] ढोफ़र विद्रोह के दौरान, चीन के विद्रोहियों का समर्थन किया, जहाँ तक बीजिंग का सवाल है, साम्राज्यवाद के विरुद्ध अरब लोगों के जन आंदोलन, फिलिस्तीनी लोगों का सशस्त्र संघर्ष और ढोफ़र में विद्रोह साम्राज्यवाद, संशोधनवाद और प्रतिक्रियावाद पर प्रहार करने वाली क्रांति में परिवर्तित हो गया।[102] विद्रोह के बाद, चीन ने ओमान के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाया और सुल्तान कबूस ने क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने की बीजिंग की क्षमता एवं राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने से पहले विश्वास- निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए इस पर सहमति जताई। चीन जहाँ होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित था और उसे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना जाता था, वहीं ओमान और अन्य खाड़ी देश ईरान और इराक द्वारा बीजिंग से सतह-से- सतह- पर मार करने वाली मिसाइलों के खरीदने से पैदा हुए मूलभूत सुविधाओं के लिए खतरे को लेकर चिंतित थे। उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं से ओमान के चीन के साथ संबंध मजबूत हुए और मस्कट अन्य खाड़ी देशों के लिए मध्यस्थ बन गया। चीन की रक्षा क्षमताओं से परिचित होने के कारण चीन को ईरान या इराक को हथियार आपूर्ति करने से रोका गया, जिसे परिणामस्वरूप बाद में

ओमान को चीन- ओमानी मैत्री में हो रहे परिवर्तन से बहुत लाभ होगा तथा संभावित रूप से दोनों पक्षों को जीत प्राप्त होगी, जिसका मुख्य कारण बीआरआई में शामिल अन्य देशों की तुलना में ओमान की अद्‌वितीय सौदेबाज़ी की स्थिति है।

युद्‌ध समाप्त हो गया। वर्तमान सुल्तान और ओमान विदेश मंत्रालय के तत्काल अवर सचिव ने युद्‌ध को समाप्त करने में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए बीजिंग की सराहना की।[103] इराक द्‌वारा कुवैत पर आक्रमण के दौरान चीन ने एक बार फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तुरंत ही 'अरब राष्ट्र और लोगों का सच्चा मित्र' बन गया।[104] उसके बाद चीन और ओमान के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध और बेहतर हुए; चीन ओमान से अपनी तेल संबंधी जरूरतों को पूरा करने में रूचि रखता था। चीन और ओमान ने 2005 से ही परस्पर संबंधित अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्‌दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक रणनीतिक बैठकें आयोजित की हैं।[105] वर्तमान में, चीन एक प्रमुख व्यापार भागीदार है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई/ BRI) के माध्यम से इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए काम कर रहा है। ओमान ने चीन की समुद्री रेशम मार्ग (मैरीटाइम सिल्क रोड) पहल को उत्साहपूर्वक अपनाया है और खुद को वैश्विक व्यापार और विनिर्माण के केंद्र में बदलने के लिए मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते प्रभाव का लाभ उठाने की उत्सुकता व्यक्त की है।[106] ओमान को चीन- ओमानी मैत्री में हो रहे परिवर्तन से बहुत लाभ होगा तथा संभावित रूप से दोनों पक्षों को जीत प्राप्त होगी, जिसका मुख्य कारण बीआरआई में शामिल अन्य देशों की तुलना में ओमान की अद्‌वितीय सौदेबाज़ी की स्थिति है।[107]

खंड II

ओमान की विदेश नीति का विकास

आज़ादी के बाद का ओमान

9 अगस्त 1970 को ओमान सुल्तान कबूस के शासन के अधीन 'ओमान की सल्तनत' बन गया, जिन्होंने अपने पिता को पद से हटा दिया और एक आधुनिक, कुशल और न्यायपूर्ण सरकार के वादे के साथ देश के प्रमुख बने। पहले 17 महीनों तक उनके चाचा तारिक बिन तैमूर ने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया और ओमान की विदेश नीति को व्यावहारिकता एवं स्थिरता के राष्ट्रीय चरित दिया। जोसेफ ए केचिचियन ने अपनी पुस्तक *ओमान एंड द वर्ल्ड* (1995) में लिखा है कि तारिक बिन तैमूर ने ओमान की विदेश नीति को सक्रिए रूप से आगे बढ़ाया और ओमान को अरब राज्यों के लीग के साथ- साथ संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश सुनिश्चित किया। वह निर्वासित इमाम ग़ालिक के साथ सुलह बैठक में भाग लेने की हद तक चले गए, जिन्होंने लीग में ओमान की इमामत का दावा किया था। साल 1972 में तैमूर के इस्तीफे के बाद, सुल्तान कबूस ने ओमान पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और सऊदी अरब जैसे पड़ोसियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए कूटनीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया, जिसमें ओमान को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने के लिए यूएनजीए वोट से परहेज किया। उन्होंने ओमान के संपर्कों का विस्तार किया तथा 60 से अधिक देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। आज, ओमान की विदेश नीति में निरंतरता और विवेकशीलता का अहम हिस्सा है; ओमान में जितनी चीज़ें बदलती हैं, उतनी ही वे एक जैसी ही रहती हैं। ओमान में निरंतरता को महत्व दिया जाता है और सूक्ष्म बदलावों को सैद्धांतिक तरीके से पेश किया जाता है। उदाहरण के लिए, 2020 में सुल्तान कबूस के निधन के बाद उनके शांत एवं सुचारू उत्तराधिकार के बाद, सुल्तान हैथम बिन तारिक

आज, ओमान की विदेश नीति में निरंतरता और विवेकशीलता का अहम हिस्सा है; ओमान में जितनी चीज़ें बदलती हैं, उतनी ही वे एक जैसी ही रहती हैं।

ने उत्तराधिकार के लिए एक नया कानून पेश किया और अपने बेटे थेयाज़िन बिन हैथम बिन तारिक अल सैद को ओमान का युवराज नियुक्त किया। इसके साथ ही, ओमान अपनी विदेश नीति में सावधानी बरतता है और लो प्रोफाइल बनाए रखता है; इसने 2012 में लीबिया के नेता मुअम्मर अल गद्दाफी के तत्काल परिवार के कुछ सदस्यों को शरण दी थी। दिसंबर 2023 में, ओमान ने लाल सागर में संचालन पर होथियों के साथ बातचीत में मध्यस्थता की थी।

अपने शासन की शुरुआत में ही सुल्तान कबूस ने ओमान की विदेश नीति के सिद्धांतों को रेखांकित किया, जिसमें अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप न करना, अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, दूसरे अरब देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करना और गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करना शामिल था। व्यावहारिकता ओमान की विदेश नीति को परिभाषित करती थी; मस्कट ने 1970 और 1980 के दशक में सुरक्षा मुद्दों पर पश्चिमी रुख के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए एक नई आर्थिक विश्व व्यवस्था की स्थापना का समर्थन किया। दूसरा, ओमान ने एक आदर्श संतुलनकारी कार्य करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, अनवर सदात के मिस्र के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, जिसने इज़रायल के साथ समझौता किया और शाह के ईरान के साथ, जिसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अमीरात के अबू मूसा और टुंब द्वीपों पर कब्ज़ा कर लिया। मस्कट ने यहूदियों के प्रति अपनी गर्मजोशी भरी नीतियों को इबादी की सहिष्णुता की नीति के आलोक में समझाया। तीसरा, ईरान के प्रति ओमान का नज़रिया उसकी भावी विदेश नीति का आधार बना। कमज़ोर होने के बावजूद, उसने ईरान को बराबर का भागीदार माना; तेहरान ने ढोफ़र युद्ध में ओमान की सहायता की और उम्मीद की कि ओमान अरब प्रायद्वीप में ईरान को बचा सकेगा।

मज़बूत स्थिति में बातचीत करने और ज़रूरत के हिसाब से समझौता करने से न सिर्फ सुल्तान कबूस एक योग्य वार्ताकार के रूप में उभरे बल्कि ओमान की छवि एक मजबूत देश के रूप में भी सामने आई जो ईरान के आगे भी नहीं झुकेगा। इसने अमीरात के द्वीपों पर ईरान के कब्ज़े

इस तथ्य को ध्यान में रखना दिलचस्प है कि सुल्तान कबूस के अधीन, ओमान उन कुछ खाड़ी देशों में से एक था, जिनकी विदेश नीति की सफलताओं ने उन्हें घरेलू सुधार शुरू करने और आंतरिक एकता को प्रेरित करने में मदद की।

और इलाके में शाह के दबंग रवैये पर चिंता व्यक्त की, साथ ही ईरान- इराक युद्ध और इराक के बाथ शासन के साथ राजनयिक संबंध तोड़े बिना कुवैत पर इराक के आक्रमण पर दुख जताया। केचिचियन कहते हैं कि बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना, उनसे बचकर रहना और ख़तरनाक एवं अक्सर ख़तरनाक परिणामों का शिकार हुए बिना समृद्ध होना ओमान की विदेश नीति की कुंजी बन गया। ओमान की विदेश नीति, जिसका उद्देश्य हितों को अधिकतम करना और ख़तरों को स्थायी रूप से न्यूनतम करना था, तात्कालिक प्रतिक्रियाओं से बचने, कभी भी राजनयिक संबंध नहीं तोड़ने और कभी भी टकराव की मंशा नहीं रखने के निर्णय द्वारा निर्देशित थी। ओमान ने कभी ईरान का सामना नहीं किया, लेकिन 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद जीसीसी के गठन में सबसे आगे था। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि सुल्तान कबूस के तहत, ओमान उन कुछ खाड़ी देशों में से एक था, जिनकी विदेश नीति में सफलताओं ने उन्हें घरेलू सुधारों को शुरू करने और आंतरिक एकता को प्रेरित करने में मदद की। सीरिया इस क्षेत्र का एक और देश है जिसने इसी तरह की घटना देखी है और पूर्व राष्ट्रपति हाफ़िज़ अल असद (1970-2000) ने विदेश नीति की सफलताओं का उपयोग वैधता को बढ़ावा देने और घरेलू क्षेत्र में सुधार लाने के लिए किया। सुल्तान कबूस ने अपने स्थिर शासन के तीसरे दशक में खाड़ी के पड़ोसी मुल्कों के साथ समझौते किए थे।

ओमान की विदेश नीति का क्रमिक- विकास

ओमान की विदेश नीति दशकों से अपने तरीके से विकसित हुई है। अपने शासन के शुरुआती दशकों के दौरान, सुल्तान कबूस ने महसूस किया कि

घरेलू सद्भाव सफल विदेश नीति के साथ समृद्ध ओमान की कुंजी थी और परिणामस्वरूप, उन्होंने बढ़ते और बड़े प्रवासी समुदाय के बोझ से निपटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।[108] ओमान की विदेश नीति मुख्य रूप से घरेलू और बाहरी कारकों के बीच अंतःक्रिया के कारण समेकन, संक्रमण, परिपक्वता और प्रगति के चार प्रमुख चरणों से गुज़री।[109] वर्ष 1970-1975 समेकन की अवधि को दर्शाता है जब ओमान को ढोफ़र विद्रोह को रोकने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और बादी के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिए अरब और गैर- अरब देशों से आर्थिक सहायता की जरूरत थी। वर्ष 1976-1980 के दौरान, ओमान उस समय संक्रमण के दौर में प्रवेश कर गया जब अपनी घरेलू परिस्थितियों को स्थिर करने के बाद सुल्तान कबूस ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। ईरान- इराक युद्ध ने ओमान को खाड़ी के राजतंत्रों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया जबकि दोनों युद्धरत देशों के साथ कार्यात्मक संबंध भी बनाए रखे।

वर्ष 1981-1985 वह अवधि है जब ओमान ने अपने विदेशी संबंधों में परिपक्वता हासिल की और जीसीसी के निर्माण में खाड़ी के राजतंत्रों के साथ एकजुट होने पर सहमति व्यक्त की, क्षेत्री. सुरक्षा गतिविधियों में भाग लिया, ईरान- इराक मुद्दे पर तटस्थ रुख बनाए रखा, पश्चिमी देशों के साथ सुरक्षा संबंधों को बनाए रखा और

अपने शासन के शुरुआती दशकों के दौरान, सुल्तान कबूस ने महसूस किया कि घरेलू सद्भाव सफल विदेश नीति के साथ एक समृद्ध ओमान की कुंजी थी और परिणामस्वरूप, उन्होंने बढ़ते और बड़े प्रवासी समुदाय के बोझ से निपटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान दिया।

अरब- इज़रायल संघर्ष को हल करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में कैंप डेविड समझौते का समर्थन किया। वर्ष 1986 से 1990 तक, ओमान ने एक प्रगतिशील चरण में प्रवेश किया, जिसमें सुल्तान कबूस ने मध्यस्थता गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इलाके में एक नेता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। ओमान ने हावर द्वीप और फश्त- अल- दिबाल प्रवालभित्ती (रीफ) के लिए बहरीन- क़तर विवाद को सुलझाने में मदद की और मिस्र- इज़रायल शांति समझौते के बाद मिस्र को अरब के पाले में वापस लाने की कोशिश की। सुल्तान कबूस ने अरब देशों को बगदाद शिखर सम्मेलन में मिस्र के शांति समझौतों को खारिज़ करने के दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभावों के बारे में चेतावनी दी और अनुमान लगाया कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में बदलाव हो रहा है जिसके परिणाम इस क्षेत्र के लिए अप्रत्याशित होने की संभावना है। दूरदर्शी होने के कारण उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ ओमान के संबंधों में सुधार किया, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए सऊदी अरब और यमन के साथ सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 1990 के बाद, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण, सोवियत संघ का विघटन, पश्चिमी देशों का बढ़ता प्रभुत्व, ईरान द्वारा कुवैत की मदद के लिए आगे आना और इसी तरह की अन्य घटनाओं ने ओमान को यह एहसास कराया कि उसे अपनी राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि क्षेत्र के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट परिवर्तन हो रहे थे। मध्यम मार्ग अपनाते हुए सुल्तान कबूस ने सद्दाम के समर्थक और विरोधी दोनों ताकतों की आलोचना की, पश्चिमी सैन्य तैनाती की अनुमति दी, कुवैती और इराकी दोनों प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया, यह आकलन किया कि न तो ईरान और न ही इज़रायल क्षेत्र के लिए तत्काल खतरा हैं और क्षेत्रीय देशों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि कुवैत के लिए युद्ध अंतिम हो और ध्यान गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित होना चाहिए।

ओमान ने विदेश नीति में साहसिक कदम उठाते हुए अन्य जीसीसी सदस्यों के रुख से स्वतंत्र होकर इज़रायल के साथ मधुर संबंध रखने की इच्छा व्यक्त की, जैसा कि 1994 के यमन गृहयुद्ध को सुलझाने में मदद करने के उसके निर्णय से स्पष्ट है।

सुल्तान कबूस ने पड़ोसी देशों के साथ ओमान के संबंधों में सुधार किया, सऊदी अरब और यमन के साथ सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई।

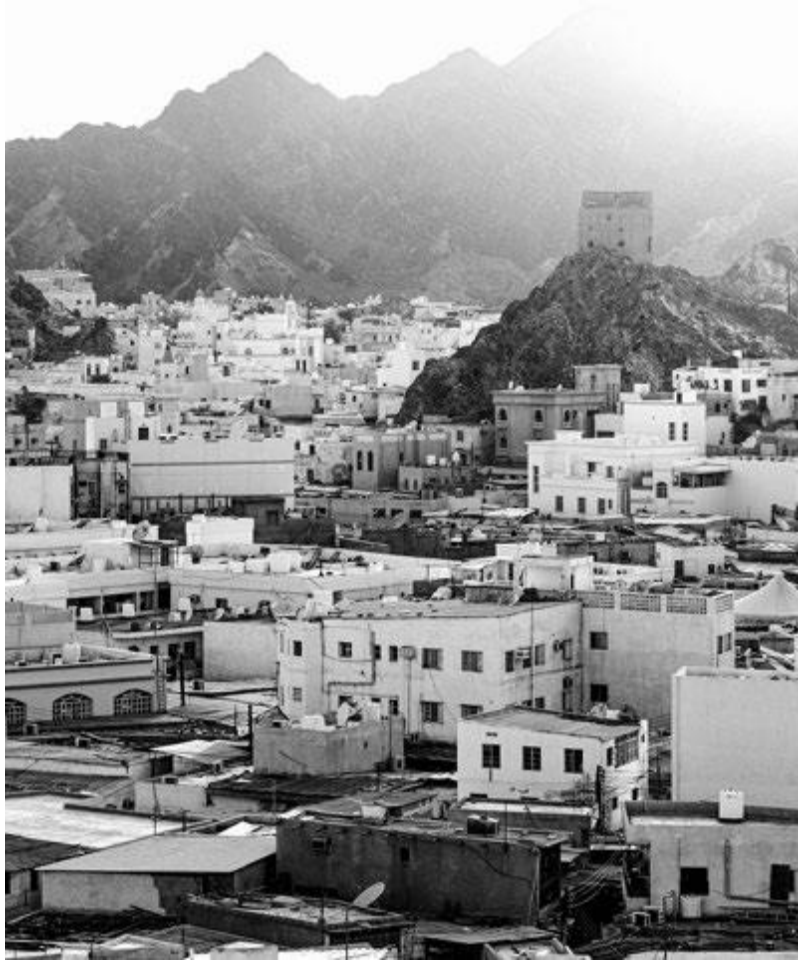

इसके अलावा, कबूस ने एक स्वतंत्र और व्यावहारिक विदेश नीति बनाए रखी, मॉस्को के साथ संबंध स्थापित करते हुए और ब्रिटेन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हुए कम्युनिस्ट- प्रेरित ढोफ़र विद्रोहियों से लड़ते हुए, अपने हथियारों की खरीद में विविधता लाई। इसी तरह, अन्य अरब देशों के विपरीत, इसने कैंप डेविड समझौते के बाद मिस्र के साथ अपने संबंध नहीं तोड़े। ओमान ने 2015 में जेसीपीओए पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तब भी जब सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे अन्य जीसीसी देशों ने इस सौदे का विरोध किया था। इसके अलावा, ओमान ने इज़रायल के प्रति नरम रुख रखने के बावजूद अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ओमान ने सुरक्षा पर महत्वपूर्ण योगदान देते हुए अंतर-जीसीसी संबंधों को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुल्तान कबूस को उनकी नेतृत्व क्षमता और सुरक्षा मुद्दों के ज्ञान के लिए जीसीसी सुरक्षा समिति का प्रमुख बनाया गया था। ओमान ने सुझाव दिया कि एक छोटे प्रायद्वीपीय ढाल बल के कुवैत की रक्षा करने में विफल होने के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा हेतु जीसीसी को 100,000 सैनिकों की एक बड़ी स्थायी सेना बनानी चाहिए। इस संदर्भ में एक छोटे देश के रूप में सुरक्षा की तलाश में ओमान द्वारा एक बड़े प्रायद्वीप शील्ड फोर्स की स्थापना पर रॉबर्ट मेसन का कार्य महत्वपूर्ण है।[110] ओमान ने विदेश नीति में साहसिक कदम उठाते हुए अन्य जीसीसी सदस्यों के रुख से स्वतंत्र होकर इज़रायल के साथ मधुर संबंध रखने की इच्छा व्यक्त की, जैसा कि 1994 के यमन गृहयुद्ध को सुलझाने में मदद करने के लिए उसके निर्णय से स्पष्ट है।

खंड III

ओमान की विदेश नीति की बदलती स्थिति

ओमान की विदेश नीति के लक्ष्य

ओमान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नीति सभी के मित्र होने के नज़रिए पर आधारित है और इस उद्देश्य से मस्कट सभी मुद्दों को संबोधित करने में मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में संवाद और सहिष्णुता को अपनाता है। सुल्तान कबूस ने आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देते हुए शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र और उससे परे ओमान की सक्रिए भागीदारी की कल्पना की थी और हैथम बिन तारिक इसी विज़न को आगे बढ़ा रहे हैं। ओमान अपने पड़ोसी देशों, जिसमें जीसीसी देश, ईरान, यमन, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं, के साथ मैत्रीपूर्ण, पारस्परिक सम्मान, अ- हस्तक्षेप और समझदारी भरे मधुर संबंध बनाए रखने में विश्वास रखता है। ओमान की विदेश नीति के उल्लेखनीय सिद्धांतों में से एक पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर ज़ोर देना है जबकि उन्हें एक- दूसरे के साथ भी ऐसे ही संबंध बनाए रखने में मदद करना है। ओमान के लिए, अपने आस- पास के इलाकों की स्थिरता उसकी अपनी सुरक्षा और दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा सिद्धांत सहिष्णुता का है और ओमान उन सभी लोगों के खिलाफ़ खड़ा होने के लिए तैयार है जो सहिष्णुता और संवाद को कमज़ोर करने या उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। तीसरा, ओमान संवाद में विश्वास करता है और संकट के समय में भी संचार के किसी भी रास्ते को बंद करने में विश्वास नहीं करता। ओमान की विदेश नीति किसी विशेष हुकूमत के हितों के पक्ष में सुरक्षा संरचना तैयार नहीं करती बल्कि एक ऐसी सुरक्षा संरचना तैयार करती है जो क्षेत्र

ओमान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नीति सभी के मित्र होने के नज़रिए पर आधारित है और इस उद्देश्य से मस्कट सभी मुद्दों को संबोधित करने में मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में संवाद और सहिष्णुता को अपनाता है।

ओमान की विदेश नीति किसी विशेष हुकूमत के हितों के पक्ष में सुरक्षा संरचना तैयार नहीं करती बल्कि एक ऐसी सुरक्षा संरचना तैयार करती है जो क्षेत्र के साथ आर्थिक और रणनीतिक रूप से जुड़े देशों के दीर्घकालिक और साझा हितों को समायोजित करती है।

के साथ आर्थिक और रणनीतिक रूप से जुड़े देशों के दीर्घकालिक और साझा हितों को समायोजित करती है।

चौथा, ओमान दुनिया के साथ अपने जुड़ाव में बाहर के देशों की ओर देखने के लिए प्रतिबद्ध है। ओमान का अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण समुद्री देशों के साथ व्यापार की अपनी लंबी परंपरा पर आधारित है। एक कदम आगे बढ़ते हुए, यह देश खाड़ी, पश्चिम एशिया और हिंद महासागर में कई देशों के साथ मधुर संबंध साझा करता है, भले ही तेज़ी से बदलते वैश्विक परिस्थितियों में दीर्घकालिक संबंध नए रूप ले रहे हों। ओमान आर्थिक वैश्वीकरण का समर्थक है और इसका लक्ष्य आने वाले दशकों में लॉजिस्टिक्स और ट्रांस- शिपमेंट के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में खुद को स्थापित करके क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार दोनों में प्रमुख भूमिका निभाना है। आखिर में, ओमान अस्थायी वैचारिक पदों के बजाय भू-रणनीतिक वास्तविकताओं पर जोर देने वाली व्यावहारिक विदेश नीति रखने में विश्वास करता है। लेकिन खाड़ी देश अपनी विदेश नीति को निर्धारित करने के लिए गुज़रती घटनाओं को अनुमति देने के प्रलोभन का विरोध करता है, क्योंकि यह अपने भू-राजनीतिक महत्व और संबंधित जिम्मेदारियों को जानाता है जो सल्तनत के होर्मुज़ जलडमरूमध्य, ओमान सागर, हिंद महासागर और अरब सागर के ऊपर स्थित होने से उत्पन्न होती हैं। ओमान जलडमरूमध्य की सुरक्षा और संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी मानता है और बदले में, पड़ोसियों एवं सभी पक्षों के साथ हर समय बातचीत बनाए रखने के पक्ष में है। उसे एहसास है कि पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता है और दीर्घकाल में, आपसी हित अल्पकालिक समस्याओं को दूर कर देंगे।

ओमान जलडमरूमध्य की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानता है और बदले में, पड़ोसियों और सभी पक्षों के साथ हर समय बातचीत बनाए रखने के पक्ष में है।

एक छोटे से देश के रूप में, ओमान की विदेश नीति बदल रही है और इसके हाल के विदेशी संबंधों के माध्यम से कुछ रुझान उभर रहे हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमी देशों के साथ अपने ऐतिहासिक और वर्तमान संबंधों के बावजूद, ओमान का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय को स्वीकार नहीं कर पाया है और अभी भी बुराई की धुरी और समृद्धि के संरक्षकों के बारे में एक द्विआधारी धारणा रखता है। कई देशों में अभी भी द्विआधारी विरोध, शून्य- योग खोल (ज़ीरो- सम गेम्स) और चयनात्मक गैर- संचार वाली शीत युद्ध मानसिकता है जो एक गंभीर बाधा और एक स्व-प्रदत्त विकलांगता के रूप में कार्य करती है। बहुध्रुवीय विश्व में कूटनीति पर ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़ में बोलते हुए ओमान के विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद बिन हामूद अलबुसैदी[111] ने कहा कि सबकी भलाई के लिए विभिन्न पक्षों के साथ संवाद करना बहुध्रुवीय विश्व में व्यावहारिक कूटनीति की कुंजी है। उन्होंने बहुध्रुवीयता को मान्यता देते हुए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के लिए ठोस प्रस्ताव दिए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी/UNSC) में सुधारों की वकालत की, कहा कि इसकी वर्तमान संरचना शीत युद्ध की एक मानवीय कला है। उन्होंने कहा कि सुधार संस्था को आज के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनाएंगे, न कि केवल आने वाले कल की समस्याओं का समाधान पेश करेंगे। दूसरा, ओमान बहुपक्षवाद का समर्थन करता है और जीसीसी, अरब लीग, इस्लामिक सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र समेत कई बहुपक्षीय संगठनों का हिस्सा है। यह हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का हिस्सा है जो हिंद महासागर क्षेत्र में निरंतर विकास और संतुलित विकास को बढ़ावा देता है।

पूर्व प्रधानमंत्री सुल्तान कबूस और उनके उत्तराधिकारी, वर्तमान सुल्तान हैथम बिन तारिक के कुशल नेतृत्व में, ओमान क्षेत्र के भीतर और बाहर सफल वार्ता के लिए एक कुशल मध्यस्थ के रूप में उभरा है।

मध्यस्थता

पूर्व प्रधानमंत्री सुल्तान कबूस और उनके उत्तराधिकारी, वर्तमान सुल्तान हैथम बिन तारिक के कुशल नेतृत्व में ओमान क्षेत्र के भीतर और बाहर अपनी सफल वार्ताओं के लिए एक कुशल मध्यस्थ के रूप में उभरा है। इसकी मध्यस्थता कौशल को सही रूप से पहचाना गया है और इसे 'सऊदी- ईरान समझौते में मध्यस्थता के लिए शांति के विवेकशील वास्तुकार'[112] और 2015 के ईरान परमाणु समझौते में मध्यस्थता के लिए 'अरब का स्विट्ज़रलैंड[113]/मध्य पूर्व [114]' के रूप में लेबल किया गया है। जेम्स वॉरल[115] जिन्होंने ओमान की मध्यस्थता गतिविधियों का विस्तार से अध्ययन किया है, कहते हैं कि यह एक 'मध्यस्थ राष्ट्र' के रूप में विकसित हुआ है जो समय के साथ विकसित हुई विश्वसनीयता की प्रतिष्ठता के माध्यम से अपनी संप्रभुता और सुरक्षा समेत ओमान की विदेश नीति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मध्यस्थता को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपयोग करता है। मोटे तौर पर, ओमान द्विपक्षीय संबंधों के प्रति अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण के कारण एक मध्यस्थ देश के रूप में उभरा है, जो अस्थायी या वैचारिक स्थितियों के बजाय दीर्घकालिक भू- रणनीतिक वास्तविकताओं पर ज़ोर देता है।[116] वॉरेल के अध्ययन में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि मध्यस्थ के रूप में ओमान का उभरना कोई साधारण घटना नहीं है; मध्यस्थता बाज़ार कतर, कुवैत, मिस्र आदि जैसे अन्य देशों से भरा पड़ा है। ओमान के मध्यस्थता प्रयास यादृच्छिक कार्य होने के बजाय एक पैटर्न का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए,

ओमान के लिए पड़ोसी देश प्राथमिकता हैं।

सुल्तान हैथम बिन तारिक सुल्तान कबूस द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता गतिविधियों को जारी रख रहे हैं।

यह अपने पड़ोसी देशों जैसे ईरान, सऊदी अरब और यमन या अपनी विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंग्डम में मध्यस्थता करता है, विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें सफलता की संभावना अधिक होती है। ओमान के लिए पड़ोस के देश प्राथमिकता हैं; यूनाइटेड किंग्डम, इंडोनेशिया, भारत और फिलीपींस की सरकारों की अपील का जवाब देते हुए, ओमान सल्तनत ने अप्रैल 2022 में यमन में बंधक बनाए गए 14 विदेशियों की रिहाई करवाई।[117]

सुल्तान हैथम बिन तारिक सुल्तान कबूस द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता गतिविधियों को जारी रख रहे हैं। वे एक व्यावहारिक यथास्थिति दृष्टिकोण का पालन कर रहे हैं, उन्होंने विदेश मंत्रालय में राजनीतिक मामलों के अवर सचिव (1986-1994) और मंत्रालय के महासचिव (1994-2002) के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। सत्ता संभालने के बाद अपने पहले भाषण[118] में सुल्तान हैथम ने ज़ोर देकर कहा कि वे अपने पूर्ववर्ती सुल्तान की विदेश नीति की विरासत का पालन करेंगे और उनके शासन में, ओमान क्षेत्र में शांति स्थापित करने, खाड़ी देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को बढ़ाने एवं अरब लीग के सदस्यों के साथ मिलकर काम करके क्षेत्र में संकटों को कम करने का गहन प्रयास करेगा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मस्कट वैश्विक राजनीति में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के संयुक्त राष्ट्र के मिशन में सक्रिए रूप से योगदान देगा और घोषणा की कि ओमान उनके पूर्ववर्ती कबूस की

सुल्तान हैथम बिन तारिक एक व्यावहारिक विदेश नीति अपनाने को दृढ़संकल्प हैं।

संतुलित और उदार विदेश नीति समझ से विचलित नहीं होगा।

क्षेत्र में कमज़ोर आर्थिक स्थिति और जारी अस्थिरता नए शासन के लिए चुनौतियां पेश करती हैं; हालाँकि, सुल्तान हैथम बिन तारिक एक व्यावहारिक विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प हैं और पेशेवरों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। सुल्तान कबूस, जिनके पास विदेश मंत्री का आधिकारिक पद था, के विपरीत, नए शासक ने बदर अल बुसैदी को ओमान का विदेश मंत्री नियुक्त किया है जो नीति निर्माण में विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। हैथम बिन तारिक के लिए, ऊर्जा संपन्न दूसरे खाड़ी देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करना, सऊदी अरब और यूएई के साथ वर्तमान तनाव को कम करना और इज़रायल, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ईरान के बीच तर्कसंगत संतुलन बनाना विदेश नीति के लक्ष्य हैं। बदर अल बुसैदी निष्पक्ष स्थिति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ओमान की तटस्थता निष्क्रिए नहीं है बल्कि रचनात्मक, सकारात्मक और सक्रिए है।[119] ओमान की मध्यस्थ भूमिका को क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने और मस्कट को प्रभावित करने की क्षमता वाली राजनीतिक कमज़ोरी को कम करने की उसकी कोशिश से समझा जा सकता है। यह ओमान की ओर से एक रक्षात्मक नज़रिया है, क्योंकि यह क्षेत्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा की तलाश को कम करता है।

विदेश नीति में समभाव

मध्यस्थता के प्रयासों के साथ- साथ, ओमान सल्तनत क्षेत्र और उससे परे दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में सकारात्मक अंतरनिर्भरता पर निर्भर करता है। अन्य देशों के साथ व्यवहार में सुल्तान कबूस के नरम और उदार दृष्टिकोण को जारी रखते हुए ओमान, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध बनाने और टकराव से बचते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने पर विचार करता है। वर्ष 1970 की शुरुआत में ही ओमान ने सुरक्षित और स्थिर फ़ारस की खाड़ी बनाए रखने और सऊदी अरब, ईरान, यूएई और यमन के साथ अपनी सीमाओं को

मध्यस्थता के प्रयासों के साथ- साथ, ओमान सल्तनत क्षेत्र और उससे परे दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में सकारात्मक अंतरनिर्भरता पर निर्भर करता है।

सुरक्षित रखने का लक्ष्य रखा था। अपनी रणनीतिक स्थिति को जानते हुए ओमान खुद को फ़ारस की खाड़ी के एक भरोसेभंद द्वारपाल के रूप में प्रस्तुत करता है और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए उसे एक सुरक्षित पड़ोसी देश की आवश्यकता है। सऊदी अरब और ईरान सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पड़ोसी देश हैं और उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध ओमान के साथ- साथ पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। नतीजतन, ओमान ने दोनों पड़ोसियों- ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौते में मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई- 2021 और 2022 में दोनों पक्षों के बीच वार्ता की मेज़बानी के लिए इराक और ओमान को धन्यवाद दिया।[120] ओमान वार्ता की मेज़बानी करने में सक्षम था क्योंकि अब उसके दोनों देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं; हालाँकि, पहले ओमान के दोनों देशों के साथ मधुर संबंध नहीं थे।

सऊदी अरब ने ओमान की अमामत के दूसरे नेता इमाम ग़ालिब को समर्थन दिया और जब तक इमाम के साथ बातचीत शुरू नहीं हुई, तब तक उसने ओमानी सुल्तान के शासन को मान्यता नहीं दी। सुलह तभी हुई जब दोनों देश खाड़ी से यूनाइटेड किंग्डम की वापसी को लेकर चिंतित हुए। साल 1971 में सुल्तान कबूस और सऊदी अरब के राजा फ़ैसल के बीच बराबरी की स्थिति बनी और सऊदी अरब ने ओमान के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन (पीडीआरवाई) के सोवियत प्रेरित

ओमान ने 1991 में तीन साल के अंतराल के बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता की थी और यह आश्चर्य की बात नहीं थी जब मार्च 2023 में चीन द्वारा अंततः समझौते के मध्यस्थता से संपन्न होने से पहले इसने दोनों खाड़ी देशों के बीच विश्वास-निर्माण वार्ता के कई दौर की मेज़बानी की थी।

खतरे को अपने लिए खतरा समझना शुरू कर दिया क्योंकि तेल के मुक्त प्रवाह के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसकी निर्भरता बढ़ती जा रही थी। हालाँकि, ढोफ़र विद्रोह के दौरान, ओमान के सैनिकों को सऊदी अरब में प्रशिक्षित किया गया था और सल्तनत को हल्के हथियार और विकास परियोजननाओं के लिए 12 मिलियन डॉलर का अनुदान प्राप्त हुआ था। साल 1975 तक, ओमान को सऊदी सहायता की कुल राशि 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई थी।

आगे चल कर, आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर और सऊदी अरब द्वारा ओमान को मानवीय सहायता प्रदान करनेक साथ सऊदी- ओमान संबंधों में सुधार हुआ। रियाद ने मस्कट और अदन के बीच युद्ध विराम की मध्स्थता की और दोनों देश अफ़गानिस्तान पर सोवियत कब्ज़े का विरोध करने पर आम सहमति में थे। वे पीडीआरवाई (PDRY) और हॉर्न ऑफ अफ़्रीका में सोवियत की बढ़ती मौजूदगी को लेकर भी चिंतित थे। उन्होंने एक आंतरिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए और सीमा समझौते की पुष्टि की।[121] ओमान ने 1991 में तीन साल के अंतराल के बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता की थी और यह आश्चर्य की बात नहीं थी जब मार्च 2023 में चीन द्वारा अंततः इस समझौते की मध्यस्थता किए जाने से पहले इसने दोनों खाड़ी देशों के बीच विश्वास- निर्माण वार्ता के कई दौर की मेज़बानी की थी।

इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ओमान ने अपने स्वतंत्र नज़रिए और संप्रभुता पर ध्यान केंद्रित करने के कारण सऊदी अरब के साथ अन्य छोटे जीसीसी देशों की तरह समान स्तर के संबंध साझा नहीं किए। इसने इराक के साथ अपने संबंधों को नहीं छोड़ा, जैसा कि सऊदी अरब ने ईरान- इराक युद्ध के दौरान किया था और बगदाद के साथ- साथ तेहरान के साथ भी तटस्थ संबंध बनाए रखे। ओमान ने न तो सऊदी किंग अब्दुल्ला के खाड़ी संघ बनाने के आह्वान पर प्रतिक्रिया दी, न ही उसने यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन में भाग लिया या न ही क़तर का बहिष्कार करने वाले सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र के चौकड़ी में शामिल हुआ। यह अरब जगत के उन कुछ देशों में से एक था जिसने संकट के दौरान सीरिया के साथ अपने राजनयिक संबंध

ओमान संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा जीसीसी व्यापारिक साझेदार है, जो जीसीसी देशों के साथ कुल अमीरात व्यापार का 20 प्रतिशत है।

नहीं तोड़े और सऊदी अरब तथा अन्य देशों द्वारा 5 वर्ष पहले तेहरान के साथ संबंध तोड़ लेने के बावजूद ईरान के साथ संबंध बनाए रखे। इसके अलावा, एक तरह से ओमान सऊदी अरब और ईरान के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने में लगा हुआ है; इसने जेसीपीओए (JCPOA) पर हस्ताक्षर करने से पहले ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वार्ता की सुविधा प्रदान की और साथ ही, आतंकवाद से लड़ने के लिए सऊदी के नेतृत्व वाले इस्लामिक सैन्य गठबंध में शामिल हो गया।

इसके अलावा, जुलाई 2021 में ओमान के सुल्तान के रूप में हैथम बिन तारिक की सऊदी अरब की पहली विदेश यात्रा में निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी के माध्यम से सहयोग के अवसरों की समीक्षा की गई [122] और तब से, संबंधों में सुधार हुआ है। दिसंबर 2021 में, सऊदी के युवराज ने अपने खाड़ी के दौरे के दौरान ओमान का दौरा किया और दोनों देशों के बीच 30 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदों पर हस्ताक्षर किए गए।[123] फिलहाल, जमीन पर बने पुल के खलने और 2021 में ओमानी- सऊदी समन्वय परिषद की स्थापना के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हो रहा है। सऊदी के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पुल से दोनों देशों के नागरिकों की सुगम आवाजाही और आपूर्ति श्रृंखलाओं का एकीकरण होगा। साल 2022 में, सऊदी के युवराज ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (पीआईएफ/PIF) को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए 5 अरब अमेरिकी डॉलर के फंड के साथ 'सऊदी- ओमानी इन्वेस्टमेंट कंपनी' बनाने के लिए प्रेरित किया।[124] जुलाई 2023 में, किंगडम के पीआईएफ ने ओमान निवेश प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे इसकी पोर्टफोलियो कंपनियों को ओमान में निवेश के अवसरों को खोलने में मदद मिलेगी।[125]

ओमान ने सऊदी अरब के साथ मिलकर फरवरी 2023 में इज़रायल को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति भी दी।[126]

ओमान के यूएई के साथ संबंधों को इस बात से समझा जा सकता है कि ओमान के सुल्तान सैद और आबू धाबी के शेख जायद के बीच घनिष्ठ संबंध थे और सुल्तान कबूस के सत्ता में आने के बाद ओमान का दौरा करने वाले शेख जायद एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष थे। ओमान ने 1971 में यूएई के निर्माण का गर्मजोशी से स्वागत किया और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से यूएई को मुसंदम प्रायद्वीप से जोड़ने वाली सड़कें बनाने का प्रस्ताव प्राप्त किया। वर्ष 1985 में, दोनों देशों ने द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए; हालाँकि यह बहुत बाद की बात थी कि दोनों देशों ने 1999 में पूर्वी उकैदाई से अल दारा तक सीमा क्षेत्रों से संबंधित सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए,[127] और दोनों देशों ने 2008 में सीमा समझौते के अंतिम सीमांकन पर हस्ताक्षर किए।[128] वर्ष 1991 में, एक संयुक्त समिति की स्थापना की गई और इसने नागरिकों को पासपोर्ट की बजाय अपने अमीरात आईडी का उपयोग कर दोनों देशों में प्रवेश करने की अनुमति दी।[129] हाल के दशकों में, संबंधों में सुधार हुआ है; उन्होंने 2020 में यूएई द्वारा अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने का समर्थन और स्वागत किया;[130] और 2 साल के बाद, 2022 में, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने ओमान का दौरा किया जिसमें हैथम बिन तारिक के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत की पुष्टि की गई। यात्रा के दौरान, आबू- धाबी निवेश कोष एडीक्यू और ओमान निवेश प्राधिकरण ने ओमान में प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेश करने के लिए 592- मिलियन दिरहम उद्यम पूंजी कोष की स्थापना करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य एवं कृषि, संचार, लॉजिस्टिक्स एवं स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में 30 अरब दिरहम के निवेश की संभावना तलाशने पर सहमति व्यक्त की।[131] दोनों देशों ने जीसीसी के बीच सहयोग के मजबूत संबंधों की इष्टतम छवि पर ज़ोर दिया।[132] ओमान यूएई का दूसरा सबसे बड़ा जीसीसी व्यापारिक साझेदार है जो जीसीसी देशों के साथ कुल अमीराती व्यापार का 20 प्रतिशत

हिस्सा है।[133] यूएई ने नवंबर 2023 में ओमान के 53वें राष्ट्रीय दिवस मनाने में ओमान के साथ भागीदारी की क्योंकि ओमान ओमान विज़न 2040 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और उसे मजबूत बनाने, प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की सतत आर्थिक वृद्धि हासिल करने, प्रति व्यक्ति औसत आय में 90 प्रतिशत तक की वृद्धि करने, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली बनाने और वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और रचनात्मकता के लिए एक राष्ट्रीय प्रणाली बनाने की योजना है जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगी। इस विज़न का एक उद्देश्य श्रम बाज़ार और रोजगार के लिए अनुकूल माहौल बनाना एवं निजी क्षेत्र को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने में सक्षम बनाना है।[134]

बहरीन, कुवैत और क़तर के साथ ओमान के संबंध खाड़ी में पश्चिम देशों के प्रभाव पर मतभेद पर आधारित है। जबकि ओमान ने अभी भी यूनाइटेड किंग्डम के साथ अपने संबंधों को बनाए रखा है, जीसीसी के दूसरे देशों ने इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को सीमित करने पर ज़ोर दिया। कुवैत ने ओमान को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसने क्षेत्रीय राजनीतिक संघ के लिए कुवैती आह्वान और खाड़ी सुरक्षा मामलों की जांच करने वाले मस्कट शिखर सम्मेलन (1976) की मेज़बानी करने के अवसर का स्वागत किया। लेकिन 1980 के दशक में, जीसीसी की छत्रछाया में इन देशों के साथ ओमान के संबंध अधिक बेहतर हुए और द्विपरक्षीय संबंधों ने सुरक्षा मुद्दों और ईरान- इराक युद्ध पर समूह बैठकों का रूप ले लिया।[135] ओमान बाहरी लोगों की मदद लेने से नहीं कतराता, जैसा कि 10वें राष्ट्रीय दिवस पर सुल्तान कबूस के भाषण से स्पष्ट है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए ओमान के पास कोई भी उपलब्ध मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने *अल माज़ल्ला* के साथ एक साक्षात्कार में दक्षिण- यमन, इथियोपिया, अफ़गानिस्तान आदि में रूस की उपस्थिति के मद्देनज़र अमेरिकी

सहायता लेने पर सहमति जताई और इसे उचित ठहराया और कहा कि इस क्षेत्र को अमेरिकी वायु सेना की आवश्यकता होगी और इसे प्रदान करने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए।

सुल्तान हैथम ने सभी पड़ोसी देशों के प्रति खुलापन दिखाया है और सभी अरब खाड़ी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना शुरू कर दिया है जिससे उस युग का अंत हो गया है जब सल्तनत को एक अलग-थलग और एकांत देश के रूप में देखा जाता था।[136] वर्तमान में, ओमान के बहरीन के साथ मधुर संबंध हैं; बहरीन की 800 से अधिक कंपनियों ने सल्तनत में निवेश किया है। दोनों देशों के निजी क्षेत्र ने मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए ओमान-बहरीन निवेश होल्डिंग कंपनी बनाने पर सहमति व्यक्त की थी।[137] संतुलित विदेश नीति अपनाने अपनाने की सुल्तान की उत्सुकता अब तक सफल साबित हुई है, खासकर अभूतपूर्व उथल- पुथल भरे वर्तमान क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्थिति के मद्देनज़र। साल 2006 में ओमानी-बहरीनी समिति की स्थापना के बाद से शिक्षा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और नगरपालिका मामलों समेत सहयोग एवं समझौते के 28 क्षेत्रों की पहचान की गई है।[138] सुल्तान हैथम बिन तारिक ने 2022 में बहरीन का दौरा किया था और दोनों पक्षों ने जीसीसी की एकजुटता को सुरक्षित करने और इसके देशों और आवाम के सहयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था ताकि वे सभी मौजूदा चुनौतियों का सामना कर सकें और जीसीसी की आर्थिक एकता को साकार कर सकें।[139] दोनों देशों ने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, निवेश, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वायु नौवहन, समुद्री परिवहन, बंदरगाह, संस्कृति, पर्यटन, अध्ययन, अनुसंधान और पर्यावरण से संबंधित अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। किंग हमाद ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में

वर्तमान में, ओमान के बहरीन के साथ मधुर संबंध हैं; बहरीन की 800 से अधिक कंपनियों ने सल्तनत में निवेश किया है।

सुल्तान हैथम ने भाईचारे के संबंधों को मजबूत करने और बहरीन- ओमान सहयोग विकसित करने में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए बहरीन के राजा को ओमान के सर्वोच्च सम्मान से नवाज़ा।

सुल्तान हैथम के प्रयासों की सराहना की, ओमान में व्यापक विकास और जीसीसी एवं पैन-अरब कार्य को बढ़ावा देने में इसकी अग्रणी भूमिका की सराहना की। किंग हमाद ने बहरीन-ओमानी संबंधों को मजबूत करने और संयुक्त सहयोग विकसित करने के उनके प्रयासों की सराहना करते हुए ओमान के सुल्तान को शेख ईसा बिन सलमान अल ख़लीफा- उत्कृष्ट श्रेणी- के खिताब से नवाज़ा। इसके बदले, सुल्तान हैथम ने भाईचारे के संबंधों को मजबूत करने और बहरीन- ओमान सहयोग विकसित करने में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए बहरीन के राजा को ओमान के सर्वोच्च सम्मान से नवाज़ा।[140] ओमान के युवराज, सैय्यद थैयाज़िन बिन हैथम बिन तारिक अल सैद ने जनवरी 2024 में बहरीन का दौरा किया था।

ओमान के मंत्रालय के अनुसार, ओमान सल्तनत और कुवैत के बीच संबंध क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय रोल मॉडल के रूप में हैं। ईमानदारी से भाईचारे और सहयोग की विशेषता वाले ये संबंध मजबूत हुए हैं और राज्यों के बीच पारंपरिक अच्छे संबंधों से आगे बढ़कर इतिहास, सामाजिक विरासत एवं दोनों देशों को एक साथ लाने वाली आम राजनीतिक स्थितियों के आधार पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। ओमान और कुवैत के बीच संबंधों की जड़ें बहुत पुरानी हैं जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण उनके बंदरगाहों के माध्यम से किया जाने वाला समुद्री संचार है। कुवैत के वाणिज्यिक जहाज़ ओमान के बंदरगाहों का प्रयोग पूर्वी एशिया, पूर्वी अफ्रीका और कई अन्य गंतव्यों की ओर जाने के लिए आरंभ स्थान के रूप में करते थे। इस संचार ने ओमानी और कुवैती लोगों के बीच सकारात्मक सामाजिक संबंध बनाने में मदद की जो आज भी जारी है। [141] कुवैत द्वारा दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैद को 'ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट'

जैसे राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करना और 2009 में दिवंगत अमीर शेख सबा अल अहमद अल ज़बर अल सवा को 'सिविल ऑर्डर ऑफ ओमान ऑफ द फर्स्ट क्लास' से सम्मानित करना , दोनों देशों के बीच गहरे सम्मान और प्रशंसा का प्रतीक है। तेल क्षेत्र, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है, में, महत्वपूर्ण सहयोग देखा गया है, विशेष रूप से OQ8 के साथ जो एक ऐसा संयुक्त उद्यम है जो आर्थिक सहयोग की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम भी है।[142] दुक़म रिफ़ाइनरी ओमान के ओक्यू (OQ) ग्रुप और कुवैत पेट्रोलियम इंटरनेशनल के बीच ओमान के दुक़म औद्योगिक क्षेत्र में 9 अरब अमेरिकी डॉलर वाला संयुक्त उद्यम है। यह रिफाइनरी उच्च गुणवत्ता वाले तेल उत्पाद प्रदान करके और ओमान की रिफाइनिंग क्षमताओं को प्रतिदिन लगभग 500,000 बैरल तक बढ़ाकर वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में एक मूल्यवान वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है।[143] फरवरी 2024 में कुवैत के अमीर की ओमान की राजकीय यात्रा उनकी दूसरी विदेश यात्रा थी। [144] दोनों देशों के लिए सबसे मजबूत क्षण वह था जब ओमान ने 1991 के इराक द्वारा कब्ज़ा किए जाने के दौरान कुवैत का समर्थन किया था और 2020 में, जब दोनों देशों ने अपने राष्ट्राध्यक्षों को खो दिया और नए शासकों ने सत्ता संभाली।[145] ओमान सल्तनत और कुवैत के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है क्योंकि दोनों देशों के नेतृत्व ने उनके बीच हस्ताक्षरित समझौतों और समझौता ज्ञापनों को सक्रिए करने के लिए प्रयास किए गए हैं। दोनों देशों का निजी क्षेत्र अपने साझा हितों को प्राप्त करने के लिए सहयोग एवं पारस्परिक निवेश के क्षेत्रों का विस्तार एवं गहन

कुवैत द्वारा दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैद को 'ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट' जैसे राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करना और 2009 में दिवंगत अमीर शेख सबा अल अहमद अल ज़बर अल सवा को 'सिविल ऑर्डर ऑफ ओमान ऑफ द फर्स्ट क्लास' से सम्मानित करना , दोनों देशों के बीच गहरे सम्मान और प्रशंसा का प्रतीक है।

करने के लिए आकर्षक क्षेत्रों में उपलब्ध निवेश अवसरों का लाभ उठाना चाहता है।[146]

ओमान- कुवैत संयुक्त समिति ने सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंधों को बहाल करने के लिए सऊदी अरब, इस्लामी गणराज्य, ईरान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा जारी संयुक्त त्रिपक्षीय बयान का स्वागत किया है। उन्होंने पुष्टि की है कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए ये कदम आवश्यक है।[147] ओमान में कुवात के राजूत मोहम्मद अल- हाज़री ने ओमान के राष्ट्रीय दिवस की 53वीं वर्षगांठ पर बधाई दी तथा कुवैत- ओमान संबंधों की गहराई की सराहना भी की।[148] कुवैत- ओमान के नए, लेकिन अभी भी अस्थिर नेता अपने पूर्ववर्तियों के समान जोखिम उठाने का खतरा नहीं मोल ले सकते।[149]

जहाँ तक ओमान- कतर संबंधों का सवाल है, ओमान में कतर के दूतावास ने कहा है कि कतर और ओमान सल्तनत के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध हैं। कतर की आज़ादी के बाद से ये संबंध सभी क्षेत्रों में मजबूत हुए हैं। वर्ष 1973 में, ओमान सल्तनत में कतर राज्य के पहले राजदूत की नियुक्ति के लिए एमिरी डिक्री नं. (2) जारी की गई थी। कतर और ओमान सल्तन के बीच द्विपक्षीय संबंधों की विशेषता स्थिरता एवं विकास है।[150] ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सैद ने नवंबर 2021 में दोहा का दौरा किया, जो इन दो खाड़ी अरब देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को रेखांकित करता है। दोनों देसों ने कराधान, बंदरगाहों, पर्यटन, रक्षा, श्रम और निवेश से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षिर किए। कोविड -19 महामारी एवं तेल की कीमतों में गिरावट के कारण ओमान गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इन समझौतों से सल्तनत के ऋण के बोझ तले दबी अर्थव्यवस्था को थोड़ी मदद मिलेगी।[151]

यमन ओमान के लिए एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी है जो किसी भी समय इसकी स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। ओमान के यमन सरकार और

ओमान और ईरान के बीच कूटनीतिक और
आर्थिक संबंध पहलवी काल से ही हैं।

हौथी विद्रोहियों दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं; यह विद्रोहियों और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीधी बातचीत की मेज़बानी भी करता है। ओमान यमन में रियाद के हस्तक्षेप को एक गलती मानता है और हूथियों को ईरानी कठपुतली के रूप में चित्रित करने वाली कहानी को खारिज़ करता है। इसके बजाय, मस्कट इस समूह को यमनी समुदाय का हिस्सा मानता है।[152] सऊदी अरब और ओमान के लिए *अल- महरा* तट के महत्व का उल्लेख करना आवश्यक है। सऊदी अरब इसे अरब सागर पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र मानता है, जो ईरान के होर्मुज़ जलडमरूमध्य के नियंत्रण से बहुत दूर है और इसे ड्रग्स एवं हथियारों की तस्करी गतिविधियों के लिए संभावित खतरा मानता है। इसका उद्देश्य सऊदी अरब से अल- महरा के तट और निश्तून बंदरगाह तक तेल ले जाने वाले एक तेल- पाइपलाइन का निर्माण करना भी था, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास अनिश्चितता के मद्देनज़र अरब सागर और हिंद महासागर तक सीधी पहुँच हो सके। दूसरी तरफ, ओमान का मानना है कि *अल-महरा* में सऊदी और अमीरात की सेना की मौजूदगी उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।[153]

केचिचियन के अनुसार, यमन वैचारिक दुश्मन के बजाय रणनीतिक सहयोगी बन गया। सुल्तान कबूस ने मई 1990 में यमन, अरब गणराज्य और पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपबल्कि ऑफ यमन के एकजुट होने और 1992 में सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। वर्तमान में, यमन ओमान के लिए मानवीय बोझ और सुरक्षा चुनौती दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। [154] यमन के शरणार्थियों और घायलों को ओमान द्वारा समायोजित करने और मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के प्रयासों से लाभ मिल रहा है। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या 4.5 मिलियन होने के कारण, यमन ओमान में शरणार्थियों की आमद का एक संभावित स्रोत है, जो निश्चित रूप से

सल्तनत की कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, यमन के अल-महरा प्रांत में सैन्यीकरण और संभावित आतंकवादी गतिविधियाँ ओमान के लिए एक बड़ी सुरक्षा चिंता का विषय हैं। अफ़रा नासर लिखते हैं कि यमन संघर्ष में इसकी भागीदारी कई चरणों से गुज़री है: सबसे पहले, इसने संघर्ष में सैन्य रूप से भाग लेने की बजाय एक संभावित शांति समझौते को पेश करना चुना और दूसरे चरण में, इसने चुपचाप पक्षों के बीच गुप्त मध्यस्थता प्रयासों का नेतृत्व किया। वर्तमान में, ओमान हूथी सशस्त्र समूह और सऊदी अरब के बीच सीधी वार्ता की मेज़बानी कर रहा है, जब से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित युद्धविराम अक्टूबर 2022 में बिना विस्तार के समाप्त हो गया था।[155]

इसी तरह, ओमान और ईरान के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंध पहलवी काल से ही हैं। ओमान का मानना है कि ईरान फ़ारस की खाड़ी के अन्य अरब देशों के लिए कोई खतरा नहीं है। सुल्तान कबूस ईरान के इस प्रस्ताव से सहमत थे कि क्षेत्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और सामूहिक सहयोग एक पूर्वापेक्षा है। कबूस ने ईरान की श्रेष्ठ सैन्य शक्ति को मान्यता दी और 1975 में महाद्वीपीय शेल्फ सीमा निर्धारण समझौता किया। जलडमरूमध्य से सुरक्षित मार्ग की आवश्यकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, ओमान ईरान को एक महत्वपूर्ण साझेदार देश मानता है। 1980 के दशक की शुरुआत में ओमान- ईरान संबंध एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गए, जब तेहरान ने ईरान- इराक युद्ध के दौरान मस्कट की रणनीतिक स्थिति की सराहना करना शुरू कर दिया और ओमान को लगा कि केवल ईरान ही इराक को संतुलित कर सकता है। ओमान ने ढोफ़र विद्रोह को दबाने में ईरान की सैन्य मदद ली थी। साल 1989 में, एक संयुक्त आर्थिक- औद्योगिक समिति का गठन किया गया था, और 1995 में जलडमरूमध्य की सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ईराम- ओमान संबंधों में उस समय खटास आई जब ईरान ने खाड़ी युद्ध के दौरान फ़ारस की खाड़ी में टैंकरों की आवाजाही पर हमले शुरू कर दिए और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज- रोधी मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए।[156] इसके बाद, ओमान ने 2007 में 15 ब्रिटिश नाविकों की रिहाई,

ईराम- ओमान संबंधों में उस समय खटास आई जब ईरान ने खाड़ी युद्ध के दौरान फ़ारस की खाड़ी में टैंकरों की आवाजाही पर हमले शुरू कर दिए और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज- रोधी मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए।

2011 में अमेरिकी कैदियों की अदला- बदली और 2015 में जेसीपीओए में ईरान को लाने का प्रयास कर, ईरान के करीब आया। दोनों देशों ने ओमान की खाड़ी में तस्करी को रोकने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। वर्ष 2022 में, ईरान के राष्ट्रपति ने ओमान का दौरा किया और इस यात्रा के बदले मई 2023 में सुल्तान हैथन ने तेहरान का दौरा किया। ओमान-ईरान संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मस्कट का एक तरफ अपने पश्चिमी पड़ोसियों और सहयोगियों के साथ एवं दूसरी तरफ तेहरान के साथ संतुलन बनाना रहा है। इसके अलावा, क्षेत्रीय सुरक्षा और ऊर्जा ईरान- ओमान संबंधों की मुख्य धुरी हैं।[157] ओमान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानता है और परमाणु समझौते के पूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मई 2023 में ओमान और ईरान के संयुक्त वक्तव्य में आर्थिक सहयोग के क्षितिज का विस्तार करने में निजी क्षेत्र की सक्रिए भूमिका पर ज़ोर दिया गया।[158] ऐसी अटकलें हैं कि ओमान जेसीपीओए के पुनरुद्धार के लिए ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक साथ लाने में सक्षम होगा। [159] दोनों देशों ने यात्रा वीज़ा में छूट दी है, जिससे पर्यटन क्षेत्र में लाभ हुआ, उड़ानों की संख्या बढ़ाई गई और 2023 के पहले 8 माह में व्यापार में 41 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। ईरान और ओमान जल्द ही एक तरजीही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग पर विचार कर रहे हैं।[160] ईरान एशियाई देशों तक अपनी गैस को पहुँचाने के लिए

ओमान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानता है और परमाणु समझौते के पूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ऐसी अटकलें हैं कि ओमान जेसीपीओए के पुनरुद्धार के लिए ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक साथ लाने में सक्षम होगा।

ओमान को एक स्टेशन के जैसा मानता है और इसके लिए दोनों देश ईरानी प्रांत होर्मोज़जान से ओमान के बंदरगाह सहर तक 260 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम करेंगे। बताया गया है कि ओमान अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में गैस का निर्यात करेगा और साथ ही अपने घरेलू बाज़ार में भी इसका इस्तेमाल कर सकेगा।[161] ओमान और ईरान के बीच व्यापार विनिमय 2022 के अंत तक 27.9 प्रतिशत बढ़ कर 320.8 मिलियन ओएमआर तक पहुँच गया।[162] ईरान की करीब 2700 कंपनियों ने ओमान में निवेश किया है।[163] मोहम्मद बिनहुवैदीन के अनुसार, ओमान रणनीतिक हेज़िंग के माध्यम से ईरान के उदय का उत्तर देता है।[164] जबकि मार्क वैलेरी के अनुसार, ओमान में शिया समूह परंपरागत रूप से शासकों के अमूल्य सहयोगी रहे हैं और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में उनके निहित स्वार्थ हैं।[165] ओमान- ईरान संबंधों का विस्तार इस तथ्य से स्पष्ट है कि दोनों देशों को आशा है कि निकट भविष्य में कुल व्यापार का आंकड़ा 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा और मार्च 2023 से जनवरी 2024 तक ओमान को गैर- तेल निर्यात 916 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।[166]

इसके विपरीत, ओमान इराक के साथ वैचारिक मतभेद में रहा, जिसने ढोफ़र विद्रोह में विद्रोहियों का समर्थन किया। इराक ने बाथिस्ट राजनीति का समर्थन किया, आरोप लगाया कि पश्चिमी शक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नव- उपनिवेशवाद का हिस्सा होने के समान थे, और जैसे कि पहले बताया गया है, ओमान ने पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे थे। इराक ने ओमान के अरब लीग में शामिल होने का विरोध किया था, लेकिन 1976 में बगदाद ने सल्तनत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। ईराक- इरान युद्ध के दौरान, ओमान ने संघर्ष के राजनयिक समाधान के लिए दबाव डालते हुए बगदाद के खिलाफ

युद्ध प्रयासों का समर्थन किया। ओमान इराक में पुनर्वास के बारे में बात करने वाले पहले कुछ देशों में एक था। वर्ष 1990 में सद्दाम हुसैन द्वारा कुवैत पर आक्रमण करने के बाद ओमान ने इराक में अपना दूतावास बंद कर दिया था। 12 मई 2019 को, ओमान ने घोषणा की कि वह बगदाद में अपना दूतावास फिर से खोलेगा।[167] वर्तमान में, ओमान तीसरा देश होगा जिसके पास इराक द्वारा ईरान को दिए जाने वाले धन का एक हिस्सा होगा, जिसका प्रयोग गैर- प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए किया जाना चाहिए। इराक और ओमान सल्तनत मिस्र और ईरान के बीच संबंधों को बहाल करने के लिए विचार- विमिर्श कर रहे हैं।[168] इराक और कुवैत रियाद एवं तेहरान के बीच राजनयिक संबंधों के सात साल के निलंबन को समाप्त करने में ओमान के सहयोगी थे।[169]

उदारवादी और नरम रुख अपनाने के बावजूद, ओमान को अपनी विदेश नीति में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और अभी भी करना पड़ रहा है। अल बुरामी ओएसिस, मुसंदम प्रायद्वीप और यमन के साथ इसकी सीमा पर इसके विवाद हैं। ओमानी एन्क्लेव माधा यूएई क्षेत्र में है जबकि यूएई क्षेत्र नाहवा ओमान से घिरा हुआ है। वर्तमान में, ओमान नौकरियों के राष्ट्रीयकरण एवं प्रवासी मुद्दे पर खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाता है। धीमी अर्थव्यवस्था और बढ़ती आबादी ने उसे नौकरियों के ओमानीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे दक्षिण एशियाई और अन्य देशों से आने वाले प्रवासियों की संख्या में कटौती हुई है। हाल के दिनों में, प्रमुख शक्तिसंपन्न देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना मुश्किल हो गया है। एक तरफ तो उसने अमेरिकी सेना को अल दुक़म और सलालाह बंदरगाहों का प्रयोग करने की अनुमति देने वाली रणनीतिक ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो दूसरी तरफ वह रूस और चीन से पूरी तरह से दूर नहीं होना चाहता। उसने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई के बावजूद रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और चीन के बीआरआई को भी अपनाया है।

उदारवादी और नरम रुख अपनाने के बावजूद, ओमान को अपनी विदेश नीति में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और अभी भी करना पड़ रहा है।

पिछले दो दशकों में ओमान ने दो बड़े विरोध प्रदर्शनों का सामना किया है: अरब क्रांति के दौरान सामाजिक सुधारों की मांग करते हुए औद्योगिक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन और 2018-2019 में आर्थिक सुधारों के लिए विरोध प्रदर्शन।

इसके अलावा, ओमान ने पिछले दो दशक में दो बड़े विरोध प्रदर्शनों का सामना किया है: अरब क्रांति के दौरान सामाजिक सुधारों की मांग करते हुए औद्योगिक श्रमिकों का विरोध और 2018-2019 में आर्थिक सुधारों के लिए विरोध प्रदर्शन। आर्थिक सुधारों और निवेश एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के माध्यम से देश की ब्रांडिंग बनाने की प्रक्रिया ने कुछ हद तक मदद की है; यूएई और क़तर की तर्ज पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आंतरिक चिंताओं के साथ- साथ, ओमान को क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी हैं; होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और संरक्षण ओमान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इज़रायल- हमास युद्ध के नतीजे इस पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि तटस्थता बनाए रखना आसान नहीं है और ओमान मुश्किल परिस्थितियों में, विशेषरूप से सऊदी अरब और ईरान से जुड़े मुद्दों पर, बहुत ही संतुलन बना कर चलता है। सऊदी- ईरान समझौते ने कुछ हद तक स्थिति को आसान बना दिया है। ओमान तटस्थता बनाए रखकर एक स्थिर पड़ोसी की अपनी दीर्घकालिक आवश्यकता को संतुलित करता है। सऊदी अरब और यमन से ओमान को घुसपैठ का ख़तरा है, जबकि क्षेत्रीय अस्थिरता देश के लिए जोखिम पैदा करती है। एक सशक्त पड़ोस के केंद्र के रूप में ओमान की स्थिति और सीरिया के मुद्दे जैसे विवादों को प्रबंधित करने की इसकी क्षमता पर ध्यान देना, कूटनीति के प्रति इसके सूक्ष्म दृष्टिकोण और तटस्थ रहने के इसके प्रयासों को उजागर करता है। ओमान की विदेश नीति का दृष्टिकोण उसके पड़ोसियों से अलग है क्योंकि क्षेत्रीय जटिलताओं के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में उसे अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष

भारत के लिए नीतिगत अनुशंसाएं

ओमान भारत के लिए एक स्वाभाविक साझेदार है, जिसने 2023 में अपनी अध्यक्षता के दौरान अतिथि देश के रूप में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ओमान को निमंत्रण दिया था। होर्मुज जलडमरूमध्य दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है; ओमान के लिए यह सुरक्षा और स्थिरता का मामला है जबकि भारत के लिए यह ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत इस क्षेत्र से तेल आयात पर बहुत अधिक निर्भर है और किसी भी तरह की गड़बड़ी से इसकी आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में भविष्य में निरंतर वृद्धि देखी जाएगी, इसके विकास के ऊपर की ओर बढ़ते प्रक्षेपवक्र को ध्यान में रखते हुए और होर्मुज जलडमरूमध्य भारत के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा, भारत और ओमान अपनी ऊर्जा निर्भरता में विविधता ला रहे हैं और हरित हाइड्रोजन में निवेश कर रहे हैं। दोनों देश इस क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइज़र उद्योग में संयुक्त उद्यमों और परियोजनाओं की और भी संभावना है। एक भारतीय इलेक्ट्रोलाइज़र कंपनी, ग्रीनजो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग कर ओमान एयरपोर्ट को रौशन करने में मदद करेगी। भारत की महारत्न कंपनी आरईसी ने ओमान में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को मंजूरी दी है, क्योंकि इसका उद्देश्य भारत मध्य- पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी/ IMEEEC) और 'एक सूरज, एक विश्व, एक ग्रिड' पहल के तहत आने वाली परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराना है। भारत इस क्षेत्र में निवेश के लिए ओमान की ओर देख रहा है, वहीं ओमान अक्षय ऊर्जा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस संदर्भ में, एक भारतीय कंपनी, एसीएमई ग्रुप ने नॉर्वे स्थित स्केटेक एएसए के साथ ओमान में अपने अमोनिया प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए समझौता किया है।

दूसरा, भारत और ओमान के बीच रक्षा सहयोग मजबूत है और स्वदेशी रक्षा क्षमता बनाने में ओमान की मदद करके इसे

होर्मुज जलडमरूमध्य दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है; ओमान के लिए यह सुरक्षा और स्थिरता का मामला है जबकि भारत के लिए यह ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत और ओमान के बीच रक्षा सहयोग मजबूत है और स्वदेशी रक्षा क्षमता बनाने में ओमान की मदद करके इसे अगले स्तर पर ले जाने की गुंजाइश है।

अगले स्तर पर ले जाने की गुंजाइश है। ओमान पहला खाड़ी देश है जिसके साथ भारतीय रक्षा बलों के तीनों अंग संयुक्त अभ्यास करते हैं। साल 2022 में, राजस्थान में 13- दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह-IV और हवाई अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज़ VI आयोजित किया गया था और द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का 13वां संस्करण ओमान के कट पर आयोजित किया गया था। दोनों देशों के बीच नियमित रूप से रक्षा संबंधी यात्राएं होती रहती हैं और जनवरी- फरवरी 2022 में ओमान के शीर्ष रक्षा अधिकारी मोहम्मद नासिर अल ज़ाबी ने भारत की आधिकारिक दौरा किया था।[170] संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (जेएमसीसी) की 12वीं बैठक में प्रशिक्षण, सुंक्त अभ्यास, सूचना साझाकरण, समुद्र विज्ञान और जहाज निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग के नए क्षेत्रों पर गहन चर्चा की गई। दोनों देशों ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक नया ढांचा प्रदान करता है। भारत के लिए ओमान में स्वेदशी रक्षा उद्योग के विकास में मदद करने की संभावना है। बदले में, ओमान ने भारत को सैन्य उपयोग और रसद सहायता हेतु दुक़म के प्रमुख बंदरगाह तक पहुँच प्रदान की है। दुक़म बंदरगाह और ड्राई डॉक भारतीय नौसैनिक जहाजों को रखरखाव प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं, जिससे भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में अपने पदचिन्हों का विस्तार करने की अनुमति मिलती है।

तीसरा, भारत और ओमान हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और संपर्क सुनिश्त करने में सहयोग करते हैं। भारत और ओमान का समुद्री व्यापार का बहुत पुराना इतिहास रहा है। व्यापार और सांस्कृतिक आदान- प्रादन को सुविधाजनक बनाने में ढो द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत और ओमान

के बीच प्राचीन और ऐतिहासिक संबंधों को प्रदर्शित करते हुए समुद्री यात्रा को फिर से बनाने का प्रस्ताव दिया है। भारत और ओमान ने 2021 में ह्वाइट शिपिंग सूचना (वाणिज्यिक गैर-सैन्य व्यापारी जहाजों की आवाजाही और पहचान के बारे में पूर्व सूचना का आदान- प्रदान) के आदान- प्रदान और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और फरवरी 2022 में संयुक्त समुद्री समिति की पहली बैठक हुई थी। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और संरक्षण ढांचे को मजबूत करने एवं अंतरराष्ट्रीय अवैध गतिविधियों से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए, दोनों देशों के तटरक्षकों ने अप्रैल 2024 में अपनी पांचवीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। दोनों देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए/ IORA) का हिस्सा हैं और समुद्री परिचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने पर केंद्रित ग्रीन शिपिंग पर सहयोग कर सकते हैं। ओमान अंतरराष्ट्रीय उत्तर- दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी/ INSTC) का भी सदस्य है, जो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच प्राप्त करने के लिए भारत की एक पहल है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1958 में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह बेचने से पहले, ओमान ने 1950 के दशक में भारत को ग्वादर बंदरगाह की पेशकश की थी। हाल के संदर्भ में, ओमान, इराक और तुर्की अपनी उपयुक्त भौगोलिक स्थिति के बावजूद आईएमईईईसी (IMEEEC) का हिस्सा नहीं हैं और भारत के लिए यह लाभदायक होगा कि वह ओमान को कनेक्टिविटी परियोजना का हिस्सा बनाने के लिए राज़ी करे, तथा इसे आईएनएसटीसी (INSTC) के विकल्प के रूप में देखे।ओमान एक समुद्री शक्ति संपन्न राष्ट्र है और भारत को इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इस क्षेत्र में इसके समर्थन की आवश्यकता है। भारत इस क्षेत्र में चीन द्वारा रणनीतिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से चिंतित है जिसमें जिबूती के पोर्ट दोरालेह में अपना बेस बनाना भी शामिल है। दूसरी ओर, ओमान इस क्षेत्र में बाहरी हितधारकों की उपस्थिति में विविधता लाने के लिए भारत में दिलचस्पी रखता है। भारत को एक बड़ी हिस्सेदारी देकर, ओमान इस क्षेत्र में एक विशाल भौतिक उपस्थिति (प्रवासी आबादी के रूप में) के साथ एक दक्षिण एशियाई अभिनेता की उपस्थिति सुनिश्चित करता है।

चौथा, भारत और ओमान के बीच मजबूत आर्थिक संबंध है; दोनों देश 2011 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शुरुआती पूंजी के साथ एक संयुक्त निवेश कोष का हिस्सा बन गए। इसके अलावा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओमान के ओक्यू एसएओसी (OQ SAOC) ने 1994 में एक संयुक्त उद्यम के रूप में बीआईएनए (BINA) तेल रिफाइनरी को शामिल किया और रिफाइनरी ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में अरब से आने वाले कच्चे तेल को संसाधित करने के लिए 6 मिलियन टन प्रति वर्ष की मूलभूत पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित की। वर्ष 2022 में, चीन के बाद भारत ओमान के कच्चे तेल के निर्यात का दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार और संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सऊदी अरब के बाद ओमान के गैर- तेल निर्यात का चौथा सबसे बड़ा बाज़ार था। दिसंबर 2023 में दोनों देशों द्वारा अपनाई गई 'भारत- ओमान संयुक्त विज़न- भविष्य के लिए साझेदारी', ओमान विज़न 2040 और 'अमृत काल' के तहत भारत के विकास उद्देश्यों के बीच तालमेल को दर्शाती है जो द्विपक्षीय साझेदारी को गहरा करने के लिए इन पूरकताओं का उपयोग करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।[171] दोनों देश भारत- ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए/CEPA) पर हस्ताक्षर करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं; भारत- ओमान सीईपीए (CEPA) के मूलपाठ पर बातचीत काफी हद तक पूरी हो चुकी है, और 'इन्वेस्ट इंडिया' द्वारा एक ओमान डेस्क बनाया जाएगा एवं 'इन्वेस्ट ओमान' द्वारा एक भारत डेस्क बनाया जाएगा। भारत और ओमान के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध मजबूत और उत्साहपूर्ण रहे हैं। वर्ष 2021-2022 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 9.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत अधिक है। साल 2021-2022 में भारत का निर्यात 3.1 अरब अमेरिकी डॉलर का था जबकि भारत ने 6.8 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया। भारत और ओमान ने तीसरे देश यानी श्रीलंका में भी निवेश किया है। ओमान के लिए, जिसकी अर्थव्यवस्था धीमी है और जो खाद्य सुरक्षा के लिए भारत पर निर्भर है, भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इसी तरह भारत के लिए भी ओमान एक विश्वसनीय और भरोसेमंद साझेदार है और सीईपीए पर हस्ताक्षर करने से शुल्कों में कमी के माध्यम से निर्यात बढ़ाने के मामले में दोनों को लाभ होगा।

भारत और ओमान सहिष्णुता के समान उदार मूल्यों को साझा करते हैं और आतंकवाद के बारे में उनकी चिंताएं एक सी हैं।

भारतीय निर्माता ओमान में अपना कारोबार लगा सकेंगे और यूरोप को हरित उत्पादों का निर्यात कर सकेंगे।

पांचवां, भारत और ओमान सहिष्णुता के समान उदार मूल्यों को साझा करते हैं और आतंकवाद के बारे में उनकी चिंताएं भी एक सी हैं। उदार इबादी परंपरागत धार्मिक और सामाजिक सहिष्णुता के साथ तालमेल बिठाती हैं जो भारत द्वारा गहराई से पोषित मूल्य है।[172] आतंकवाद का मुकाबला भारत और ओमान की बीच साझा चिंता का विषय है। साल 1994 से, जब मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा सुल्तान कबूस को सत्ता से हटाने की साज़िश का पर्दाफाश हुआ, ओमान ने आतंकवाद और कट्टरपंथ के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है, और भारत, आतंकवाद के साथ अपने बुरे इतिहास को देखते हुए, भी, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। दोनों देश समान राजनीतिक मूल्यों को भी साझा करते हैं जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने वाले प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखाते हैं। भारत और ओमान सभी देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचने और बातचीत एवं कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से संघर्षों को हल करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं। दोनों देशों ने मनी लॉन्ड्रिंग, संबंधित अपराधों और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित खुफिया जानकारी के आदान- प्रदान में सहयोग के लिए वित्तीय खुफिया इकाई और राष्ट्रीय वित्तीय सूचना केंद्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत और ओमान आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तों की निंदा करते हैं तथा इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी कारण से किसी भी आतंकवादी कृत्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हैं तथा शांति, संयम, सह- अस्तित्व और सहिष्णुता के सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करते हैं,

साल 2008 से रणनीतिक साझेदार होने के साथ- साथ भारत और ओमान के बीच समृद्ध और गहरे संबंध भी हैं।

साथ ही सभी प्रकार के हिंसक उग्रवाद को त्यागने की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हैं।

साल 2008 से रणनीतिक साझेदार होने के साथ- साथ भारत और ओमान के बीच एक समृद्ध और गहरा सौहार्दपूर्ण संबंध भी है। दोनों देशों की आवाम के बीच संपर्क 5000 साल पुराना है, जबकि राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित हो गए थे। सिंधि घाटी सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य ओमान में पाए गए हैं और ओमान के व्यापारी 7वीं शताब्दी में गुजरातियों के जहाज निर्माण कौशल पर निर्भर थे।[173] ओमान में 700,000 ज्यादा भारतीय रहते हैं और कुछ भारतीय परिवार 150- 200 सालों से भी अधिक समय से वहाँ पर रह रहे हैं। पूर्वी भारत के खोजा और सिंध के भट्टिया से लेकर पेशेवरों की वर्तमान पीढ़ी तक, भारतीय प्रवासी समुदाय ने ओमान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसा कि ओमानी सरकार अक्सर स्वीकार करती है।[174] साल 1988 में 'ओमानीकरण' की नीति शुरू करने के बावजूद, ओमान ने भारतीय प्रवासी श्रमिकों का गर्मजोशी से स्वागत किया है। जून 2018 में, ओमान ने उन भारतीयों को आगमन पर वीज़ा देने की अपनी नीति की घोषणा की जिनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंगेन या जापान का वैध वीज़ा है।[175] इसी प्रकार, ओमान के कई नागरिक भारत में रहकर पढ़ाई की है। सुल्तान तैमूर बिन फ़ैसल 1932 में भारत आए और आजीवन यहीं रहे। उन्हें मुंबई में सुपुर्दे- खाक किया गया था। सुल्तान सईद बिन तैमूर और फ़हद बिन तैमूर ने अज़मेर के मेयो कॉलेज में पढ़ाई की है।

भारत और ओमान भी इन संबंधों को बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं; दोनों देशों ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है और ओमान के मध्य पूर्व में आयुर्वेद के लिए एक केंद्रीय केंद्र बनने की संभावना

भारत और ओमान के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र, दुर्लभ पृथ्वी खनिज़ों और साइबर सुरक्षा में सहयोग के अवसर हैं।

पर चर्चा की है। योग भारत और ओमान को जोड़ने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक है; भारत ने अप्रैल 2022 में "मस्कट योग महोत्सव- 75- दिन, 75- कार्यक्रम" शीर्षक से योग मैराथन का शुभारंभ किया और अपने समकक्षों के साथ मिलकर 'आत्मीय योग- शांत ओमान' शीर्षक से एक छोटा वीडियो जारी किया, जिसमें योग को पर्यटन को बढ़ावा देने के माध्यम के रूप में उपयोग किया गया था।[176] भारत और ओमान सतत पर्यटन में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके पर्यटन में सहयोग बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हिन्दी में भारतीय अध्यन के आईसीसीआर चेयर की स्थापना के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और ढोफर विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओमान भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी/ ITEC) कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित स्थानों का भरपूर लाभ उठा रहा है।[177] जहाँ तक विचार मंच सहयोग का सवाल है, दोनों देशों ने ओमान के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) और भारत के रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), भारत के ओमानी राजनयिक संस्थान और विदेश सेवा संस्थान, ओमान के राज्य लेखा परीक्षा संस्थान एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के बीच सगयोग हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आखिर में, भारत और ओमान के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र, दुर्लभ पृथ्वी खनिज़ों और साइबर सुरक्षा में सहयोग के अवसर हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच साझा हितों को रेखांकित करते हुए, दोनों देशों ने रिमोट सेंसिंग, उपग्रह प्रक्षेपण और संचार एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोगों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग की विशाल क्षमता को पहचाना है। ओमान के एक प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दौरा किया,

जब विशेष रूप से ओमान से संबंधित उपग्रह डेटा, भू- स्थानिक परतों और मूल्यवर्धित सेवाओं को शामिल करने के लिए वेब- आधारित जीआईएस पोर्टल लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष क्षेत्र भारत के लिए कई अवसर खोल सकता है जो अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ रहा है और ओमान जो इस क्षेत्र में सहयोग करने और लाभ उठाने की इच्छा रखता है। भारत के विकासात्मक और अन्य उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों एवं अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास में अपनी क्षमताओं के विकास में ओमान को अपनी मदद की पेशकश की। भारत और ओमान ने 2018 में अंतरिक्ष सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन एवं 2021 में खनिज संसाधनों के दोहन हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने निवेश के अवसरों, उत्खनन के आधुनिक तरीकों की खोज और तकनीकी अनुसंधान एवं भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहयोग बढ़ाने के बारे में आंकड़े साझा करने पर भी सहमति व्यक्त की है। ओमान की 50 प्रतिशत से अधिक भूमि खनिजों से भरपूर चट्टानों से पटी हुई है और भारत चौथी औद्योगिक क्रांति से जुड़े खनिजों की खोज करने का इच्छुक है। भारत और ओमान कोबाल्ट, तांबा, निकल और वैनेडियम में सहयोग पर विचार कर सकते हैं।

दिसंबर 2023 में, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने भारत की आधिकारिक यात्रा की और समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, पर्यटन और कृषि एवं खाद्य सुरक्षा समेत लगभग 10 प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने हेतु एक विज़न दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए। यह ओमान के सुल्तान की 26 वर्षों में पहला भारत दौरा था, और

भारत और ओमान के लिए अनंत अवसर और संभावनाएं हैं और यह मधुर संबंध यह सुनिश्चित करता है कि आने वाले दशकों में इस क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाएगा।

दिसंबर 2023 में हैथम की भारत दौरे के दौरान हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य के अनुसार,[178] नागरिक उड्डयन और हवाई संपर्क सहयोग के लिए एक और क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं। ओमान ने आपसी लाभ के लिए हवाई क्षेत्र एवं हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली अनुकूलन के लिए मिलकर काम करने में दिलचस्पी दिखाई है। दोनों देशों के बीच प्रत्येक सप्ताह 400 से अधिक सीधी उड़ानें हैं। भारत और ओमान के लिए अनंत अवसर और संभावनाएं हैं और सॉफ्ट कनेक्शन यह सुनिश्चित करता है कि आने वाले दशकों में क्षमता का पूरा उपयोग किया जाएगा।

अंतिम टिप्पणी

1 Links to Small States Forum Members Information by Country, The World Bank, May 2021, available at https://thedocs.worldbank.org/en/doc/922761504726183951-0290022020/original/CountrylinksofSmallStates.pdf (Accessed on September 08, 2023).

2 The Commonwealth Member Countries, available at https://thecommonwealth.org/our-member-countries (Accessed on September 08, 2023).

3 Andrea O Suilleabhain, Small States at the United Nations: Diverse Perspectives, Shared Opportunities, New York: International Peace Institute, May 2014 available at https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/ipi_e_pub_small_states_at_un.pdf (Accessed on September 12, 2023).

4 Ministry of Foreign Affairs, Singapore, available at https://www.mfa.gov.sg/SINGAPORES-FOREIGN-POLICY/International-Organisations/G20#:~:text=Singapore%20has%20usually%20been%20invited,and%20the%20broader%20UN%20membership. (Accessed on September 12, 2023).

5 United Nations, Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, available at https://www.un.org/ohrlls/content/about-small-island-developing-states (Accessed on September 12, 2023).

6 Jeffrey Willis, Pacific Dynamics: Journal of Interdisciplinary Research, Breaking the paradigm(s): A review of the three waves of international relations small state literature, Vol 5, No. 1, 2021.

7 Jeanne A.K. Hey (ed), Small States in World Politics: Explaining Foreign Policy Behavior, Lynne Rienner Publishers.

8 Tom Long, Small States, Great Power? Gaining Influence Through Intrinsic, Derivative, and Collective Power, International Studies Review, Volume 19, Issue 2, June 2017, pp. 185–205.

9 The Characteristics of Small States, available at https://www.thecommonwealth-ilibrary.org/index.php/comsec/catalog/download/713/713/5356?inline=1 (Accessed on September 15, 2023).

10 Ksenia Efremova, Small States in Great Power Politics. Understanding the "Buffer Effect", Central European Journal of International and Security Studies 13, No. 1, pp. 100–121.

11 Alfred Marleku, Small States Foreign Policy: The Case of Kosovo, Alternatives, Turkish Journal of International Relations, Vol. 11, No. 3, Fall 2012, pp. 79–97.

12 Idris Demir, National Securities of Small States in The International System, KMU, IIBF, Vol 10, No. 14, 2008.

13 B Thorhallsson, A. Wivel, Small states in the European Union: what do we know and what would we like to know?, Cambridge Review of International Affairs, Vol. 19, No. 4, 2006, pp. 651–668.

14 Miriam Fendius Elman, The Foreign Policies of Small States: Challenging Neorealism in Its Own Backyard, British Journal of Political Science, Cambridge University Press, Vol. 25, No. 2, April 1995, pp. 171–217.

15 Susi Dennison, Does size matter? Small states and EU foreign policy, European Council on Foreign Relations, 12 February 2013, available at https://ecfr.eu/article/commentary_does_size_matter_small_states_and_eu_foreign_policy/ (Accessed on September 20, 2023).

16 Yun Yi Lai, Explaining Small States Foreign Policy in Contemporary Southeast Asia Using Structural Realism Theory: Cases of Cambodia, Singapore and Vietnam, Nanyang Technological University, available at https://dr.ntu.edu.sg/handle/10356/138793 (Accessed on September 20, 2023).

17 Annette Baker Fox, The Power of Small States, University of Chicago Press, 1959, p. 211.

18 Gezim Vallasi, Small States in Europe and the Changing International Order, Geneva Centre for Security Policy, 18 May 2023, available at https://www.gcsp.ch/publications/small-states-europe-and-changing-international-order (Accessed on September 25, 2023).

19 Baldur Thorhallsson and Sverrir Steinsson, Small State Foreign Policy, Politics, 24 May 2017, available at https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-484 (Accessed on September 26, 2023).

20 Informal High-level roundtable on "Small States, Multilateralism and International Law", Remarks by H.E. Mr. Abdulla Shahid, President of the 76th session of the United Nations General Assembly, 28 April 2022 available at https://www.un.org/pga/76/2022/04/28/informal-high-level-roundtable-on-small-states-multilateralism-and-international-law/ (Accessed on September 28, 2023).

21 Giorgi Gvalia, David Siroky, Bidzina Lebanidze, and Zurab Iashvili, Thinking Outside the Bloc: Explaining the Foreign Policies of Small States, Security Studies, Vol. 22, No. 98, 2013, p.131.

22 Archie W Simpson, Realism, Small States and Neutrality, E-International Relations, 5 February 2018, available at https://www.e-ir.info/2018/02/05/realism-small-states-and-neutrality/ (Accessed on September 28, 2023).

23 Kristin Haugevik, Piret Kuusik, Kristi Raik, Niels Nagelhus Schia, Small States, Different Approaches Estonia and Norway on the UN Security Council, November 2021, available at https://icds.ee/ wp-content/uploads/2021/11/ICDS_EFPI_Report_Small_States_Different_Approaches_Haugevik_Kuusik_Raik_Schia_November_2021.pdf (Accessed on October 01, 2023).

24 Neal G. Jesse, John R. Dreyer, Small States in the International System: At Peace and at War, Rowman and Littlefield, available at https://rowman.com/ISBN/9781498509718/Small-States-in-the-International-System-At-Peace-and-at-War (Accessed on September 08, 2023).

25 Nicholas J. Spykman, Geography and Foreign Policy, II, The American Political Science Review, Vol. 32, No. 2, April 1938, pp. 213-236.

26 Country Studies, US Library of Congress, available at https://countrystudies.us/persian-gulf-states/45.htm (Accessed on October 02, 2023).

27 Observatory Patrimoine d'Orient, available at https://patrimoinedorient.org/index.php/en/2022/01/26/omans-maritime-and-shipbuilding-heritage/ (Accessed on October 02, 2023).

28 Ministry of Defence, Oman, available at https://www.mod.gov.om/en-US/MSC/PAGES/NAVY.ASPX (Accessed on October 02, 2023).

29 Ahmad A. Al Futaisi, Oman Maritime Heritage, Ministry of Transport and Communications, March 2019, available at https://asyad.om/docs/default-source/publications/oman-maritime-heritage-(eng)-.pdf?sfvrsn=68cf8ca8_2#:~:text=archaeological%20the%20third%20millennium%20BC&text=Construction%20of%20boats%20and%20ships,(3000%2D1300%20BC).&text=Oman%2C%20known%20as%20%E2%80%9CMajan%E2%80%9D,hubs%20in%20the%20ancient%20world.&text=Merchants%20were%20skilled%20in%20maritime%20navigation (Accessed on October 04, 2023).

30 Oman Territorial Disputes, Country Studies, US Library of Congress, available at https://countrystudies.us/persian-gulf-states/45.htm (Accessed on October 02, 2023).

31 CIA, The World Factbook, available at https://cia.gov/the-world-factbook/countries/oman/#people-and-society (Accessed on October 08, 2023).

32 Ahmed Al-Ismaili, Ethnic, Linguistic, and Religious Pluralism in Oman: The Link with Political Stability, Al Muntaqa, Arab Center for Research & Policy Studies, Vol. 1, No. 3, December 2018, pp. 58-73.

33 J. E. Peterson, Oman's Diverse Society: Northern Oman, Middle East Journal, Vol 58, No. 01, Winter 2004.

34 Oman most tolerant in Gulf Cooperation Council, Times of Oman, 26 September 2016, available at https://timesofoman.com/article/18178-oman-most-tolerant-in-gulf-cooperation-council (Accessed on October 10, 2023).

35 Jeremy Jones and Nicholas Rideout, Oman, Culture, and Diplomacy, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.

36 M. Mazharul Islam, Demographic transition in Sultanate of Oman: Emerging Demographic Dividend and Challenges, Middle East Fertility Society Journal, Vol. 25, No. 7, 2020.

37 Mai Al Abri, Population Touches 4982568, Oman Observer, 23 February 2023, available at https://www.omanobserver.om/article/1133221/oman/population-touches-4982568 (Accessed on October 10, 2023).

38 International Monetary Fund, 2022, available at https://www.imf.org/en/Countries/OMN (Accessed on October 10, 2022).

39 GDP to grow by 5.6 per cent in 2022, Oman Observer, 20 April 2022, available at https://www.omanobserver.om/article/1118082/oman/gdp-to-grow-by-56-in-2022 (Accessed on October 20, 2023).

40 Expats Banned from Several Job Positions in Oman, Zawya 2021, available at https://www.zawya.com/en/economy/expats-bannedfrom-several-job-positions-in-oman-uef09o9a (Accessed on October 20, 2022).

41 The new Labour Law: 15 key decisions for Omanis and expats, Times of Oman, 25 July 2023, available at https://timesofoman.com/article/133937-the-new-labour-law-15-key-decisions-for-omanis-and-expats (Accessed on October 20, 2023).

42 Labour Law, Ministry of Manpower, Sultanat of Oman, 2012.

43 Ministry of Finance, Oman.

44 Lakshmi Priya, Labour Sector Reforms in the GCC and Challenges for Indian Expatriates, Manohar Parrikar Institute for Defence Studies & Analyses, 27 November 2020, available at https://www.idsa.in/issuebrief/labour-sector-reforms-in-the-gcc-lpriya-271120 (Accessed on October 20, 2023).

45 Vinod Nair, Oman Imposes Ban on Hiring Expats for 207 Professions, Oman Observer, 17 July 2022, available at https://www.omanobserver.om/article/1122288/oman/labour/oman-imposes-ban-on-hiring-expats-for-207-professions (Accessed on October 25, 2023).

46 Oman clamping down on work visas for female expat professionals, 19 September 2023, available at https://www.expatsblog.com/news/1909167079/female-expat-professionals-facing-problems-applying-for-oman-work-visas (Accessed on October 25, 2023).

47 Arsalan Tariq, Oman Expat Recruitment Rules and Recent Restrictions, BSA, available at https://bsabh.com/knowledge-hub/news/oman-expat-recruitment-rules-and-recent-restrictions (Accessed on October 25, 2023).

48 Jeffrey A. Lefebvre, Oman's Foreign Policy in the Twenty-First Century, Middle East Policy Council, 15-18 February 2009, available at https://mepc.org/journal/omans-foreign-policy-twenty-first-century (Accessed on September 08, 2023).

49 Zawawy Group, available at https://www.zawawigroup.com/founder/ (Accessed on October 25, 2023).

50 Sigurd Neubauer, From Nasserite to top diplomat of Oman: Yusuf bin Alawi, Man and Culture, 07 May 2022 available at https://manandculture.com/2022/05/from-nasserite-to-top-diplomat-of-oman-yusuf-bin-alawi/ (Accessed on October 25, 2023).

51 Ahmed Hamoud Al-Maamiry, Oman and East Africa, Lancers Publishers, New Delhi, p. 104.

52 Country Studies, US Library of Congress, available at https://countrystudies.us/persian-gulf-states/49.htm (Accessed on October 10, 2023).

53 International Trade Administration, Oman-Country Commercial Guide, available at https://www.trade.gov/country-commercial-guides/oman-oil-gas#:~:text=In%20June%202022%2C%20the%20Ministry,around%2024%20trillion%20cubic%20feet (Accessed on October 10, 2023).

54 Oman oil discoveries to boost production by up to 100,000 barrels, minister says, Reuters, 04 June 2022, available at https://www.reuters.com/markets/commodities/oman-oil-discoveries-boost-production-by-up-100000-barrels-minister-2022-06-04/ (Accessed on October 10, 2023).

55 Oman 2040, Vision Document

56 Oman's Renewable Energy Projects, 27 April 2020, International Trade Administration, available at https://www.trade.gov/market-intelligence/omans-renewable-energy-projects (Accessed on October 10, 2023).

57 Jomar Mendoza, Oman's First Waste to Energy Plant Attracts Environmentally Conscious Investors, Oman Observer, 28 August 2023, available at https://www.omanobserver.om/article/1142003/business/energy/omans-first-ever-waste-to-energy-plant-attracts-environmentally-conscious-investors (Accessed on October 10, 2023).

58 Renewable Energy, International Trade Administration, 20 February 2024, available at https://www.trade.gov/country-commercial-guides/oman-renewable-energy (Accessed on October 28, 2023).

59 Oman Direct Investment Abroad, CEIC, available at https://www.ceicdata.com/en/indicator/oman/direct-investment-abroad#:~:text=Oman%20Direct%20Investment%20Abroad%20expanded,USD%20mn%20throughout%20the%20period (Accessed on October 28, 2023).

60 Adnan Aamir, Oman Offer to Build Gwadar Railway Conjures Pakistan Port's Past, Nikkei Asia, 24 August 2022, available at https://asia.nikkei.com/Spotlight/Belt-and-Road/Oman-offer-to-build-Gwadar-railway-conjures-Pakistan-port-s-past#:~:text=The%20investment%20would%20be%20worth,of%20the%20Gulf%20of%20Oman (Accessed on October 28, 2023).

61 Oman Oil Minister Excited to be Part of Sri Lanka Oil Refinery Project, Reuters, 25 March 2019, available at https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/oman-oil-minister-excited-to-be-part-of-sri-lanka-oil-refinery-project/68557482 (Accessed on October 28, 2023).

62 Oman interested to invest in Bangladesh, say visiting officials, The Business Standard, 24 March 2022, available at https://www.tbsnews.net/dropped/trade/oman-interested-invest-bangladesh-say-visiting-officials-390846 (Accessed on October 28, 2023).

63 Oman Inks 10-year Gas Export Deal With Bangladesh, Zawya, 22 June 2023, available at https://www.zawya.com/en/business/energy/oman-inks-10-year-gas-export-deal-with-bangladesh-oencebu9 (Accessed on October 28, 2023).

64 Haider Abdul Redha Al Lawati, Africa, A Promising Market for Omani Products, Oman Observer, 08 March 2023, available at https://www.omanobserver.om/article/1133829/opinion/business/africa-a-promising-market-for-omani-products (Accessed on October 28, 2023).

65 Kabeer Yousuf, Syria Seeks Oman Investments, 03 April 2023, Oman Observer, available at https://www.omanobserver.om/article/1135114/business/economy/syria-seeks-oman-investments (Accessed on October 28, 2023).

66 Nepali envoy to Oman seeks investment from Oman to Nepal, Khabar Hub, 17 September 2020, available at https://english.khabarhub.com/2020/17/128147/ (Accessed on October 28, 2023).

67 Oman seeks investment in green energy from Italy, Switzerland, Times of Oman, 25 June 2023, available at https://timesofoman.com/article/132662-oman-seeks-investment-in-green-energy-from-italy-switzerland (Accessed on October 28, 2023).

68 Oman seeks investments from Malaysia, New Straits Times, 06 November 2014, available at https://www.nst.com.my/news/2015/09/oman-seeks-investments-malaysia (Accessed on October 28, 2023).

69 Oman seeks investments through stimulus package, Zawya, 18 October 2022, available at https://www.zawya.com/en/world/middle-east/oman-seeks-investments-through-stimulus-package-gvp0ev7u (Accessed on October 28, 2023).

70 2021 Investment Climate Statements: Oman, US Department of States, available at https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/oman/ (Accessed on October 28, 2023).

71 Austin G Commons, 'Revisiting Oman: A Model for Integrating Conventional and Special Operations Advisors in Security Force Assistance', Small Wars Journal, 11 August 2020.

72 Diego Lopes da Silva, Nan Tian, and Alexandra Marksteiner, 'Trends in World Military Expenditure, 2020'. SIPRI, April 2021

73 Pieter D. Wezeman, Justine Gadon And Siemon T. Wezeman, Trends in International Arms Transfers, 2022, SIPRI Factsheet, March 2023, available at https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-03/2303_at_fact_sheet_2022_v2.pdf (Accessed on September 08, 2023).

74 J. E. Peterson, Oman in the Twentieth Century: Political Foundations of an Emerging State, Croom Helm London, 1978, pp. 136-151.

75 Sultanate Of Oman Donates US $ 3 Million for UNRWA to Support Palestinians in Need in The Gaza Strip, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Available at https://www.unrwa.org/newsroom/news-releases/sultanate-oman-donates-us-3-million-unrwa-support-palestinians-need-gaza-Strip (Accessed on September 08, 2023).

76 Oman Reiterates Commitment to Provide Aid for Yemen, Oman News Agency, 03 March 2024, available at https://omannews.gov.om/topics/en/80/show/4536 (Accessed on March 04, 2024).

77 Oman sends over 80 tonnes of aid to Libya, Muscat Daily, 19 September 2023, available at https://www.muscatdaily.com/2023/09/19/oman-sends-over-80t-of-aid-to-libya/ (Accessed on September 23, 2023).

78 Oman Extends Humanitarian Medical Aid to Lebanon Amid Challenging Times, Lebanon News, 17 August 2023, available at https://www.lbcgroup.tv/news/lebanon-news/718738/oman-extends-humanitarian-medical-aid-to-lebanon-amid-challenging-time/en (Accessed on September 08, 2023).

79 Oman sends aid to Somalia, Relief Web, 19 February 2012, available at https://reliefweb.int/report/somalia/oman-sends-aid-somalia (Accessed on September 08, 2023).

80 Anirban, Oman sends humanitarian aid to Pakistan, Muscat Daily, 19 September 2022, available at https://www.zawya.com/en/world/middle-east/oman-sends-humanitarian-aid-to-pakistan-grw6s1gf (Accessed on September 08, 2023).

81 Sultanate of Oman sets up an air bridge to transport relief and medical aid to Syria, Syrian News Agency, 08 February 2023, available at https://www.sana.sy/en/?p=299532 (Accessed on September 08, 2023).

82 HM issues Royal Orders to provide relief aid to Morocco, Times of Oman, 11 September 2023, available at https://timesofoman.com/article/135898-hm-issues-royal-orders-to-provide-relief-aid-to-morocco-1 (Accessed on September 15, 2023).

83 Oman sent 975 tonnes of aid this year to affected nations, Muscat Daily, 20 August 2023, available at https://www.zawya.com/en/economy/gcc/oman-sent-975-tonnes-of-aid-this-year-to-affected-nations-orjy5g8w (Accessed on September 08, 2023).

84 The Two Sides of Aid Diplomacy, Centre on Public Diplomacy, available at https://uscpublicdiplomacy.org/pdin_monitor_article/two-sides-aid-diplomacy (Accessed on September 23, 2023).

85 Oman gets $1bn in aid from Qatar, Financial Times, 28 October 2020, available at https://www.ft.com/content/8ba9e58f-3c66-45f3-8417-0cb39f3a9083 (Accessed on September 08, 2023).

86 U.S. Relations With Oman, US Department of State, 12 May 2022, available at https://www.state.gov/u-s-relations-with-oman/ (Accessed on September 08, 2023).

87 Oman secures $3.55 billion loan from Chinese banks, Gulf State Analytics, available at https://gulfstateanalytics.com/august-2017-3/#:~:text=A%20group%20of%20Chinese%20financial,revenue%20from%20lower%20oil%20prices. (Accessed on September 08, 2023).

88 Gulf Cooperation Council (GCC), Ministry of External Affairs, Government of India, available at https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Gulf_Cooperation_Council_MEA_Website.pdf (Accessed on September 08, 2023).

89 Oman 'Not leaving the GCC': Official, Gulf News, June 27, 2016, available at https://gulfnews.com/world/gulf/oman/oman-not-leaving-the-gcc-official-1.1853457 (Accessed on January 08, 2024).

90 Giorgio Cafiero, Brett Sudetic, Oman's Diplomatic Moves in Syria, Carnegie, 17 December 2020, available at https://carnegieendowment.org/sada/83486 (Accessed on January 08, 2024).

91 Giorgio Cafiero, Oman Breaks from GCC on Yemen Conflict, Al Monitor, 07 May 2015, available at https://www.al-monitor.com/originals/2015/05/oman-response-yemen-conflict.html (Accessed on January 15, 2024).

92 Omani FM calls for "Arab intervention" in Libya, Reuters, 12 March 2011, available at https://www.reuters.com/article/libya-arabs-oman-idUSLDE72B09520110312/ (Accessed on Accessed on January 15, 2024).

93 Isolated Qatar signs agreements with Oman, Arab News, 28 January 2018, available at https://www.arabnews.com/node/1234946/business-economy (Accessed on Accessed on January 15, 2024).

94 Country Studies, available at https://countrystudies.us/persian-gulf-states/67.htm (Accessed on Accessed on January 15, 2024).

95 J. A. Kechichian, Oman and the World: The Emergence of an Independent Foreign Policy, RAND, 1995, p. 152.

96 US Magazine Interview of Sultan Qaboos Reported FBIS-MEA-V-83-226, 20 December 1983, pp. C1-C2, In J. A. Kechichian, Oman and the World: The Emergence of an Independent Foreign Policy, RAND, 1995, p. 153.

97 Jeff Gerth and Judith Miller, US is said to Develop Oman as its Major Ally in the Gulf, The New York Times, 25 March 1985, pp. A1-A8, In J. A. Kechichian, Oman and the World: The Emergence of an Independent Foreign Policy, RAND, 1995, p. 154.

98 The United States and the Sultanate of Oman: Two Centuries of Friendship, US Embassy in Oman, available at https://om.usembassy.gov/our-relationship/us-oman-relationship/ (Accessed on Accessed on January 15, 2024).

99 U.S. Statement on the Signing of the Strategic Framework Agreement, US Embassy in Oman, available at https://om.usembassy.gov/u-s-statement-on-the-signing-of-the-strategic-framework-agreement/#:~:text=On%20March%2024%2C%202019%2C%20the,ports%20in%20Salalah%20and%20Duqm. (Accessed on Accessed on January 15, 2024).

100 Press release on Foreign Minister Sergey Lavrov's talks with Foreign Minister of the Sultanate of Oman Sayyid Badr bin Hamad Albusaidi, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, available at https://mid.ru/en/maps/om/1896377/ (Accessed on Accessed on January 15, 2024).

101 Donald Hawley, Oman and its Renaissance, London and New Jersey, Stacey International, 1990, p. 19. In J. A. Kechichian, Oman and the World: The Emergence of an Independent Foreign Policy, RAND, 1995, p. 186.

102 Yitzhak Shichor, The Middle East in China's Foreign Policy, 1949-1977, New York, Cambridge University Press, 1979, p. 152, In J. A. Kechichian, Oman and the World: The Emergence of an Independent Foreign Policy, RAND, 1995, p. 188.

103 Omani Official Delegation Arrives in Beijing, FBIS-CHI-88-187, 27 September 1988, p.19, In J. A. Kechichian, Oman and the World: The Emergence of an Independent Foreign Policy, RAND, 1995, p. 195.

104 More on Visit by Omani Foreign Affairs Advisor, FBIS-CHI-90-198, 12 October 1990, p.10, In J. A. Kechichian, Oman and the World: The Emergence of an Independent Foreign Policy, RAND, 1995, p. 196.

105 Historical Exchanges and Future Cooperation Between China and Oman Under the “Belt & Road” Initiative, International Relations and Diplomacy, January 2018, Vol. 6, No. 01, pp.1-15, available at https://davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/5aa9ca508dc8e.pdf (Accessed on February 08, 2024).

106 Mordechai Chaziza, The Significant Role of Oman in China’s Maritime Silk Road Initiative, Contemporary Review of the Middle East, December 2018, Vol. 6, No. 1, available at https://www.researchgate.net/publication/329923223_The_Significant_Role_of_Oman_in_China's_Maritime_Silk_Road_Initiative (Accessed on February 12, 2024).

107 Available at https://afkarjournal.files.wordpress.com/2019/11/afkar-1.1-printsmith-sino-omani-relations-in-the-age-of-the-belt-and-road-initiative.pdf (Accessed on February 12, 2024).

108 J. A. Kechichian, Oman and the World: The Emergence of an Independent Foreign Policy, RAND, 1995, p. 56.

109 J. A. Kechichian, Oman and the World: The Emergence of an Independent Foreign Policy, RAND, 1995, pp. 249–250.

110 The Omani Pursuit of a Large Peninsula Shield Force: A Case Study of a Small State's Search for Security ROBERT MASON, British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 41, No. 4 (OCTOBER 2014), pp. 355-367 (13 pages), Published By: Taylor & Francis, Ltd.

111 Foreign Minister lecture at Oxford Centre for Islamic Studies, Foreign Ministry of Oman, 15 February 2024, available at https://www.fm.gov.om/foreign-minister-lecture-at-oxford-centre-for-islamic-studies/ (Accessed on February 17, 2024).

112 Benjamin Barthe, Oman acts as a discreet architect of peace in the Middle East, Le Monde, 13 July 2023, available at https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/07/13/oman-a-discreet-architect-of-peace-in-the-middle-east_6052064_4.html (Accessed on February 12, 2024).

113 Richard Engel, Iran’s Supreme Leader Personally Set Conditions for Nuclear Deal: Negotiator. NBC News, 28 January 2016, available at https://www.nbcnews.com/news/world/iran-s-supreme-leader-personally-set-conditions-nuclear-deal-negotiator-n506001 (Accessed on February 12, 2024).

114 Saric Khalid, What’s Next for the “Switzerland of the Middle East”? The McGill International Review, 23 December 2018, available at https://www.mironline.ca/whats-next-for-the-switzerland-of-the-middle-east/ (Accessed on February 12, 2024).

115 James Worrall, “Switzerland of Arabia”: Omani Foreign Policy and Mediation Efforts in the Middle East, The International Spectator, Vol. 56, No. 4, December 2021, p. 134-150, available at https://www.iai.it/en/pubblicazioni/switzerland-arabia-omani-foreign-policy-and-mediation-efforts-middle-east (Accessed on February 12, 2024).

116 Jones, Jeremy, and Ridout, Nicholas, Oman, Culture, and Diplomacy, 2012, Edinburgh: Edinburgh University Press.

117 Oman Earns Recognition as Trusted Mediator, Unipath, 18 August 2023, available at https://unipath-magazine.com/oman-earns-recognition-as-trusted-mediator/ (Accessed on February 12, 2024).

118 Abdulgani Bozkurt, Muhammed Hüseyin Mercan, Oman’s Foreign Policy and Its Mediating and Balancing Role in the Middle East, Marmara University Journal of Political Science, Vol. 10, No. 1, March 2022.

119 Art Hinshaw, Oman: An Emerging International Mediator, Indisputably, 24 October 2023, available at http://indisputably.org/2023/10/oman-an-emerging-international-mediator/ (Accessed on February 12, 2024).

120 Iran, Saudi thank Oman for facilitating talks, Muscat Daily, 11 March 2023, available at https://www.muscatdaily.com/2023/03/11/iran-saudi-thank-oman-for-facilitating-talks/ (Accessed on September 08, 2023).

121 Oman/Saudi Arabia Boundary, Oman/Yemen Boundary, Office of the Geographer, Department of State, available at https://hiu.state.gov/cartographic_guidance_bulletins/09-Oman-Saudi%20Arabia-1993.pdf (Accessed on February 12, 2024).

122 A Joint Statement from the Sultanate of Oman and the Kingdom of Saudi Arabia, Foreign Ministry of Oman, 07 December 2021, available at https://www.fm.gov.om/a-joint-statement-from-the-sultanate-of-oman-and-the-kingdom-of-saudi-arabia/ (Accessed on September 08, 2023).

123 Saudi Arabia, Oman sign deals worth $30 billion, The Economic Times, 07 December 2021, available at https://economictimes.indiatimes.com/news/international/saudi-arabia/saudi-arabia-oman-sign-deals-worth-30-bn/articleshow/88142027.cms?from=mdr (Accessed on October 08, 2023).

124 Margarita Arredondas, Saudi Arabia and Oman Agree to Further Strengthen Bilateral Partnership, 07 February 2023, Atalayar, available at https://www.atalayar.com/en/articulo/politics/saudi-arabia-and-oman-agree-further-strengthen-bilateral-partnership/20230207115503160059.html (Accessed on February 16, 2024).

125 Saudi Arabia enhances cooperation with Oman as PIF signs MoU with OIA, Arab News, 27 July 2023, available at https://www.arabnews.com/node/2345161/business-economy (Accessed on February 16, 2024).

126 Oman joins Saudi Arabia in Allowing Israeli Carriers to Use its Airspace, Financial Times, available at https://www.ft.com/content/547bd5a7-1baa-41a9-b16a-f831b2e7a797 (Accessed on February 19, 2024).

127 Ministry of Foreign Affairs, United Arab Emirates, available at https://www.mofa.gov.ae/en/Missions/Muscat/UAE-Relationships/Bilateral-Relationship (Accessed on February 16, 2024).

128 Historic UAE-Oman Accord Involves 272 km of Border, Gulf News, 22 July 2008, available at https://gulfnews.com/uae/government/historic-uae-oman—accord-involves-272km-of-border-1.119592 (Accessed on September 08, 2023).

129 Mina Aldroubi, UAE-Oman Relations Set to be Further Strengthened by Sheikh Mohamed Visit, The National News, 26 September 2022, available at https://www.thenationalnews.com/gulf-news/oman/2022/09/26/uae-oman-relations-set-to-further-strengthened-Dr. Lakshmi Priya is a Research Fellow at the Indian Council of World Affairs. She is an expert in Middle East Studies with experience in policy-oriented think tanks in India. She has published several articles and contributes write-ups on the geopolitical and socio-economic issues of the region frequently. Her published catalogue also includes articles immersed in the Gramscian idea of cultural hegemony and Galtung's idea of positive peace in the region. Before her fellowship at the Indian Council of World Affairs, she worked as Research Analyst at the Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses.-sheikh-mohamed-visit/ (Accessed on September 08, 2023).

130 Ali Abo Rezeg, Oman welcomes UAE-Israel Agreement, 14 August 2020, AA, available at https://www.aa.com.tr/en/middle-east/oman-welcomes-uae-israel-agreement/1941688 (Accessed on September 08, 2023).

131 UAE, Oman to Boost Trade and Investment Ties, Reuters, 28 September 2022, available at https://www.reuters.com/world/middle-east/uae-oman-boost-trade-investment-ties-2022-09-28/ (Accessed on September 08, 2023).

132 Ministry of Foreign Affairs, United Arab Emirates, available at https://www.mofa.gov.ae/en/Missions/Muscat/UAE-Relationships/Economic-Cooperation (Accessed on September 08, 2023).

133 UAE joins Oman in celebrating its 53rd National Day, WAM-Emirates News Agency, 17 November 2023, available at https://www.wam.ae/en/article/apoqfj7-uae-joins-oman-celebrating-its-53rd-national-day (Accessed on December 23, 2023).

134 Ibid.

135 J. A. Kechichian, Oman and the World: The Emergence of an Independent Foreign Policy, RAND, 1995, p. 83.

136 On visit to Bahrain, Oman's Sultan seeks to develop ties, The Arab Weekly, 24 October 2022, available at https://thearabweekly.com/visit-bahrain-omans-sultan-seeks-develop-ties (Accessed on September 08, 2023).

137 Oman, Bahrain Relations Deeply Entrenched in History, Constantly Consolidated by Fraternal Bonds, Oman News, 22 October 2023, available at https://omannews.gov.om/topics/en/79/show/110482/dark (Accessed on September 08, 2023).

138 On visit to Bahrain, Oman's Sultan Seeks to Develop Ties, The Arab Weekly, 24 October 2022, available at https://thearabweekly.com/visit-bahrain-omans-sultan-seeks-develop-ties (Accessed on October 24, 2023).

139 Joint statement from Oman and Bahrain, Foreign Ministry of Oman, 25 October 2022, available at https://www.fm.gov.om/joint-statement-from-sultanate-of-oman-and-kingdom-of-bahrain/ (Accessed on September 08, 2023).

140 Bahrain, Oman Hail Historic Relations, Sign Several Agreements, Gulf News, 25 October 2022, available at https://gulfnews.com/world/gulf/bahrain/bahrain-oman-hail-historic-relations-sign-several-agreements-1.91501559 (Accessed on March 08, 2024).

141 Oman and Kuwait – A Model of Brotherly Relations, 04 February 2024, available at https://www.fm.gov.om/oman-and-kuwait-a-role-model-for-brotherly-relations/ (Accessed on March 04, 2024)

142 Oman-Kuwait Relations Flourishing Unhindered, Muscat Daily, 07 February 2024, available at https://www.muscatdaily.com/2024/02/07/oman-kuwait-relations-flourishing-unhindered/ (Accessed on March 04, 2024).

143 Kuwait, Oman Further Boost Partnership, Gulf Cooperation, 7 February 2024, Asharq Al-Awsat, available at https://english.aawsat.com/gulf/4838911-kuwait-oman-further-boost-partnership-gulf-cooperation (Accessed on March 04, 2024).

144 Oman Kuwait Ties Constitute Role Model for Solid Relations, Oman Observer, 04 February 2024, available at https://www.omanobserver.om/article/1149206/oman/oman-kuwait-ties-constitute-role-model-for-solid-relations (Accessed on March 04, 2024).

145 Kuwaiti-Omani ties: History of Brotherhood, Strong cooperation, KUNA-Kuwait News Agency, 05 February 2024, available at https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3135593&language=en (Accessed on March 10, 2024).

146 Remarkable Growth in Economic Ties Between Oman and Kuwait, Times of Oman, 04 February 2024, available at https://timesofoman.com/article/141604-remarkable-growth-in-economic-ties-between-oman-and-kuwait (Accessed on March 10, 2024).

147 Pooja Chandak, Oman and Kuwait Discusses Bilateral Cooperation in Renewable Energy Sector, Solar Quarter, 17 March 2023, available at https://solarquarter.com/2023/03/17/oman-and-kuwait-discusses-bilateral-cooperation-in-renewable-energy-sector/#google_vignette (Accessed on August 17, 2023).

148 Kuwait Ambassador congratulates Oman on 53rd National Day, Kuwait Times, 18 November 2023, available at https://kuwaittimes.com/article/7979/kuwait/other-news/kuwait-ambassador-congratulates-oman-on-53rd-national-day/ (Accessed on March 10, 2024).

149 Cinzia Bianco, The Deaths of the Mediators-in-Chief: Oman, Kuwait, and De-escalation in the Gulf, European Council on Foreign Relations, 09 October 2020, available at https://ecfr.eu/article/commentary_the_deaths_of_the_mediators_in_chief_oman_kuwait_and_de_escalati/ (Accessed on September 28, 2023).

150 Qatar-Oman Relations, Qatar Embassy in Muscat, available at https://muscat.embassy.qa/en/oman/qatar-oman-relations (Accessed on November 14, 2023).

151 Giorgio Cafiero, Omani Sultan's First Official Visit to Qatar Highlights Growing Ties, TRT World, available at https://www.trtworld.com/opinion/omani-sultan-s-first-official-visit-to-qatar-highlights-growing-ties-52198 (Accessed on September 08, 2023).

152 Abdulaziz Kilani, The Limits of a Saudi-Omani Rapprochement, New Lines Institute, 01 September 2021 available at https://newlinesinstitute.org/strategic-competition/regional-competition/hed-the-limits-of-a-saudi-omani-rapprochement/ (Accessed on September 08, 2023).

153 Mohaamed Alragavi, Saudi Arabia, Oman compete for control in Yemen's Mahra, AA, 05 January 2021, available at https://www.aa.com.tr/en/middle-east/saudi-arabia-oman-compete-for-control-in-yemen-s-mahra/2098447 (Accessed on September 08, 2023).

154 Ibrahim Jalal, The War Next Door: Omani Foreign Policy Toward Yemen, Middle East Institute, 21 September 2023, available at https://www.mei.edu/publications/war-next-door-omani-foreign-policy-toward-yemen (Accessed on September 28, 2023).

155 Afrah Nasser, Oman's Interests and Role in the Conflict in Yemen, Arab Centre Washington DC, 14 March 2023, available at https://arabcenterdc.org/resource/omans-interests-and-role-in-the-conflict-in-yemen/(Accessed on September 08, 2023).

156 Will Fulton, Oman-Iran Foreign Relations, Critical Threats, 22 February 2010, available at https://www.criticalthreats.org/analysis/oman-iran-foreign-relations (Accessed on September 08, 2023).

157 Umud Shokri, Regional security and energy are the main axes of Iran-Oman relations, MENA Affairs, 13 June 2022, available at https://menaaffairs.com/regional-security-and-energy-are-the-main-axes-of-iran-oman-relations/ (Accessed on September 08, 2023).

158 Oman and Iran issue joint statement, Foreign Ministry of Oman, 29 May 2023, available at https://www.fm.gov.om/oman-and-iran-issue-joint-statement/ (Accessed on September 08, 2023).

159 Why is Oman's Sultan in Iran and Will it See The Revival of JCPOA?, Iran International, 29 May 2023, available at https://www.iranintl.com/en/202305299397 (Accessed on September 08, 2023).

160 Farzad Ramezani Bonesh, Iran-Oman Relations, Opportunities, Challenges and Prospects, Middle East Political and Economic Institute, available at https://mepei.com/iran-oman-relations-opportunities-challenges-and-prospects/ (Accessed on September 08, 2023).

161 What is Unique About the Omani-Iranian Relations?, Centre for Iranian Studies, 26 August 2016, available at https://iramcenter.org/en/what-is-unique-about-the-omani-iranian-relations-957 (Accessed on September 08, 2023).

162 Omani-Iranian relations witness remarkable growth, Zawya, 25 May 2023, available at https://www.zawya.com/en/economy/gcc/omani-iranian-relations-witness-remarkable-growth-uh37bv9g (Accessed on September 08, 2023).

163 Oman-Iran: 50 Years of Strong Relations, Oman Observer, 21 May 2022, available at https://www.omanobserver.om/article/1119486/oman/his-majesty/oman-iran-50-years-of-strong-relations (Accessed on September 08, 2023).

164 Mohammed Binhuwaidin (2019) Oman's Response to a Rising Iran: A Case of Strategic Hedging, Journal of Arabian Studies, Vol. 9, No.1, pp. 1-12.

165 M. Valeri, Iran-Oman Relations Since the 1970s: A Mutually Beneficial Modus Vivendi, In A. Ehteshami, N. Quilliam, G. Bahgat, (eds) Security and Bilateral Issues between Iran and its Arab Neighbours, 2017, Palgrave Macmillan.

166 Iran-Oman Trade Ties, Tehran Times, available at https://www.tehrantimes.com/tag/Iran-Oman+trade+ties (Accessed on March 02, 2024).

167 US Says Oman Will be Conduit in Iraqi Debt Payments To Iran, Iran International, 25 July 2023, available at https://www.iranintl.com/en/202307257326 (Accessed on September 08, 2023).

168 Iraq, Oman Mediate to Restore Relations Between Egypt And Iran – Reports, Middle East Monitor, 12 April 2023, available at https://www.middleeastmonitor.com/20230412-iraq-oman-mediate-to-restore-relations-between-egypt-and-iran-reports/ (Accessed on September 08, 2023).

169 Tom Hussain, Oman Looks to Raise Profile in Asia After Helping Saudi Arabia And Iran Bury The Hatchet, South China Morning Post, 16 April 2023, available at https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3217161/oman-looks-raise-profile-asia-after-helping-saudi-arabia-and-iran-bury-hatchet (Accessed on November 08, 2023).

170 Shubhajit Roy, Explained: India, Oman ties and why it's top defence official's Delhi visit important, The Indian Express, 31 January 2022, available at https://indianexpress.com/article/explained/explained-india-oman-ties-defence-officials-mohammed-nasser-al-zaabi-delhi-visit-7748422/ (Accessed on September 08, 2023).

171 India, Oman Adopt Vision Document to Expand Ties, 18 December 2023, The Economic Times, available at https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-oman-adopt-vision-document-to-expand-ties/articleshow/106046745.cms?from=mdr (Accessed on September 08, 2023).

172 Lakshmi Priya, India-Oman Relations: A Product of Historical And Contemporary Political, Economic And Cultural Bonds, Diplomatist, Special Publication, 2018, available at https://idsa.in/system/files/news/Diplomatist-Magazine-Oman%2B2018-lpriya.pdf (Accessed on September 08, 2023).

173 Pasha, A K (1999), Tipu Sultan's Relations with Oman, in India and Oman (ed.) by A K Pasha, Gyan Sagar Publications, p. 7.

174 India and Oman Bilateral Relations, Embassy of India, Oman, available at https://www.indemb-oman.gov.in/eoi.php?id=bilateral#:~:text=The%20Sultanate%20of%20Oman%20is,enjoy%20warm%20and%20cordial%20relations. (Accessed on September 08, 2023).

175 Lakshmi Priya, India-Oman Relations: A Product of Historical And Contemporary Political, Economic And Cultural Bonds, Diplomatist, Special Publication, 2018, available at https://idsa.in/system/files/news/Diplomatist-Magazine-Oman%2B2018-lpriya.pdf (Accessed on September 08, 2023).

176 Yoga Gaining Popularity in Oman Shows New Video by Indian Embassy, The Print, 20 June 2023, available at https://theprint.in/world/yoga-gaining-popularity-in-oman-shows-new-video-by-indian-embassy/1634644/ (Accessed on September 18, 2023).

177 India-Oman Relations, Ministry of External Affairs, Government of India, available at https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/26_Oman_November_2017.pdf (Accessed on September 08, 2023).

178 India - Oman Joint Statement during the State Visit of His Majesty Sultan Haitham bin Tarik of the Sultanate of Oman, Ministry of External Affairs, Government of India, 16 December 2023, available at https://www.mea.gov.in/incoming-visit-detail.htm?37457/India++Oman+Joint+Statement+during+the+State+Visit+of+His+Majesty+Sultan+Haitham+bin+Tarik+of+the+Sultanate+of+Oman (Accessed on January 15, 2024).

लेखक के बारे में

डॉ. लक्ष्मी प्रिया भारतीय वैश्विक परिषद में शोध अध्येता हैं। ये भारत में नीति- उन्मुख विचार मंच में अनुभव के साथ मध्य- पूर्व अध्ययन में विशेषज्ञ हैं। इनके अनेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं और क्षेत्र के भू- राजनीतिक एवं सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर अक्सर ये लेख लिखती रहती हैं। इनकी प्रकाशित सूची में ग्राम्सियन सांस्कृतिक आधिपत्य के विचार और क्षेत्र में सकारात्मक शांति के गैलटुंग के विचार से जुड़े लेख भी शामिल हैं। भारतीय वैश्विक परिषद में अपनी फेलोशिप से पहले, उन्होंने मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में शोध विश्लेषक के रूप में काम किया है।

SAPRU HOUSE PAPER

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली 110 001, भारत

दूरभाष: +91-11-23317246, फैक्स: +91-11-23320638

www.icwa.in